नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मासिक समाचार पत्र • वर्ष 4 अंक 3
अप्रैल 2002 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

विपक्ष के नपुंसक विरोध और संसदीय गुलगपाड़े के बीच आतंकवाद निरोधक कानून पर संसद की मुहर

(संपादक)

लखनऊ। दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र होने का दम भरने वाले देश की संसद ने जनतांत्रिक अधिकारों को रौंद देने वाले अब तक के सबसे अधिक जनविरोधी काला कानून **आतंकवाद विरोधी कानून (पोटा)** पारित कर दिया है। देश भर में जनतांत्रिक अधिकार संगठनों और खुद सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विरोध को दरकिनार करते हुए 26 मार्च को बुलाये गये संसद के संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल के सहारे भाजपा सरकार अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो गयी।

यही है पूंजीवादी जनतंत्र की महिमा! जाति-धर्म का खेल खेलकर, पैसे और बन्दूकों की नोक के सहारे चुनाव जीतकर "जनप्रतिनिधि" बने थैलीशाहों के टट्टुओं, भ्रष्टाचारियों-अपराधियों का बहुमत जनता के बहुमत पर इसी तरह सवारी गांठता है। देशी-विदेशी मुनाफाखोरों के नुमाइन्दे इसी तरह जनता के नुमाइन्दे बनकर एक से बढ़कर एक जनविरोधी कानूनों को जनता पर थोपते चले जाते हैं और जनता जनतंत्र का झुनझुना भी ठीक से बजाने लायक नहीं रह जाती।

कहने को संसदीय विपक्ष अपनी पीठ ठोंक सकता है कि उसने राज्यसभा में पोटो को नहीं पास होने दिया और अपने बूते उसने संयुक्त अधिवेशन में बारह घण्टे तक गर्मागर्म बहस चलायी। लेकिन इस नपुंसक बहस से पोटा लाने के पीछे सरकार की मंशा उजागर होने से अधिक यह उजागर हुआ कि ऐसे दमनकारी कानूनों से संसदीय विपक्षियों को कोई उसूली विरोध नहीं है। आज जनता की नजरों में सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में खड़े दिखायी देना उनकी मजबूरी है। दमनकारी कानूनों पर कांग्रेस का भरोसा तो पहले ही उजागर हो चुका है। भारत रक्षा अधिनियम (डी.आई.आर.), आन्तरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम (मीसा), राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका), आतंकवाद एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक अधिनियम (टाडा) – ये सभी दमनकारी कानून कांग्रेसी शासन की ही देन रहे हैं। इमर्जेंसी के काले दिनों की सौगात कांग्रेस ने ही दी थी। इसलिए पोटा के खिलाफ संयुक्त अधिवेशन में कांग्रेसियों द्वारा चलायी गयी बहस जनता के अधिकारों की हिमायत का ढोंग था।

रही बात दूसरे विपक्षी दलों की तो उनकी स्थिति भी कांग्रेसियों से किसी तरह अलग नहीं है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पोटा जैसे दमनकारी कानून या तो लागू हैं या लागू करने की कोशिश हो चुकी है। महाराष्ट्र में 'मकोका' कानून (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) लागू है जिसके प्रावधान पोटा से कम दमनकारी नहीं है। इसी तरह का कानून पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वाम मोर्चे के दूसरे घटक दलों की खींचतान के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में जनान्दोलनों पर कितनी लाठियां-गोलियां चलीं इसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। थोड़े में कहें तो यह कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विपक्षी दलों ने आतंकवाद निरोधक कानून के खिलाफ जनता के जनतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत का तेवर अपनाते हुए जो बहस चलायी वह सिर्फ इस मजबूरी में थी कि भाजपा सरकार से नाराज जनता की भावनाएं अपने पक्ष में कर सकें।

सच बात तो यह है कि पोटा जैसे दमनकारी कानूनों की जरूरत आज सिर्फ भाजपा ही नहीं पूरे शासक वर्ग को है। शासक वर्ग को मुख्य खतरा आतंकवाद से नहीं है। वह डरा हुआ है भविष्य से। जनता को तबाही-बर्बादी की ओर तेज रफ्तार से धकेलती जा रही जिन नीतियों पर शासक वर्ग चल रहा है उससे भविष्य में प्रचण्ड जनविस्फोटों की भूमिका लिखी जा रही है। शासक वर्ग इसी बात से डरा हुआ है। उसकी मजबूरी यह है कि वह

(पेज 6 पर जारी)

होण्डा पावर प्रोडक्ट के मजदूरों ने आरपार की लड़ाई के लिए कमर कसी

अवैध तालाबन्दी और मजदूरों का आन्दोलन जारी

रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर), 3 अप्रैल। होण्डा पावर प्रोडक्ट लि. में कारखाने की शिफ्टिंग की योजना और गैरकानूनी तालाबन्दी के खिलाफ मजदूरों का संघर्ष अब नये दौर में प्रवेश कर चुका था। जैसी कि पहले से ही उम्मीद थी, 3 अप्रैल की वार्ता का नाटक भी विफलता में समाप्त हो गया। प्रशासन और श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों ने कारखाना प्रबंधन के साथ मिलकर यूनियन के नेताओं को उल्लू बनाने और धमकाने की भरपूर कोशिश की पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। संघर्ष के इस आर-पार के दौर में मजदूर अब अपने परिवारों के साथ कूद पड़े हैं। पूरे इलाके की व्यापक आम जनता, विभिन्न जनसंगठन और यूनियनें भी उनके समर्थन में और मजबूती से खड़ी होती जा रही हैं।

तीन अप्रैल को उत्तरांचल के श्रम सचिव सुबह आठ बजे कारखाने का निरीक्षण करने आने वाले थे, लेकिन अपने काफिले सहित वे डेढ़ बजे पधारे। उपश्रमायुक्त यूनियन प्रतिनिधि को एक गेट से बुलाकर ले गये, पर उससे मिले बिना श्रम सचिव महोदय दूसरे गेट से बाहर हो गये। अपराह्न तीन बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर वार्ता शुरू हुई जिसमें यूनियन और मैनेजमेण्ट के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रशासन की ओर से श्रम सचिव, श्रमायुक्त, उपश्रमायुक्त, डी.एम., एस.एस.पी. और सिटी मजिस्ट्रेट शामिल हुए। वार्ता में श्रम सचिव पूरी तरह से मैनेजमेण्ट की भाषा बोलते रहे। मैनेजमेण्ट को ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा।

3 अप्रैल की वार्ता विफल, प्रबंधन और प्रशासन की मिलीभगत और धोखाधड़ी

इस तरह से पूरा मामला एकतरफा रहा। यहां तक कि कार्यवाही में यूनियन का पक्ष ही दर्ज नहीं किया गया। बस, इतना लिख दिया गया कि यूनियन सहयोग नहीं कर रहा है। वार्ता की विफलता के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने यूनियन नेताओं को सीधे -सीधे डण्डा चलाने की धमकी भी दी। इस घटना ने इसी सच्चाई को एकदम साफ कर दिया कि इस देश के हुक्मरान देशी पूंजीपतियों के टट्टू तो हैं ही, अब वे खुलेआम साम्राज्यवादियों के लठैत की भी भूमिका निभा रहे हैं और दहशतगर्दी कर रहे हैं।

इसके पूर्व विगत एक अप्रैल को कारखाना गेट पर हुई मजदूरों की सभा में करीब बारह सौ लोग इकट्ठा हुए थे जिनमें करीब तीन सौ महिलाएं भी थीं। सभा में **बिगुल मजदूर दस्ता, संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा, क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन, दिशा छात्र संगठन** और **मजदूर किसान संघर्ष समिति** के अतिरिक्त कई ट्रेड यूनियन नेता और स्थानीय नेता भी शामिल हुए थे।

उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल को ही दिल्ली से आई **'पीपुल्स यूनियन**

(पेज 6 पर जारी)

भीतर के पन्नों पर

1. कंट्रोल्स ग्रुप्स के मजदूरों की पहल उम्मीद जगाती है -पृ. 3
2. बार्सिलोना में विश्वपूंजीवाद के मुंह पर कालिख पुती - पृ. 4
3. देउबा की भारत यात्रा - पृ. 4
4. पार्टी की बुनियादी समझदारी - पृ. 7
5. चीन में खुले बाजार की नीतियों का चमत्कार-पृ. 8
5. दिल्ली नगर निगम चुनाव - पृ. 9
6. गुजरात में खून की होली खेलने वाले ... - पृ. 12

बजा बिगुल मेहनतकश जाग, चिंगारी से लगेगी आग!

आपस की बात

एकजुटता ही हमारी ताकत

तीन साल तक एक एक्सपोर्ट गारमेण्ट फैक्टरी में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुझे काम पर से इसलिए निकाल दिया गया कि जिस सिलाई मशीन पर मैं काम करता था, उसकी नीडिल की चुटकी कहीं गिर गयी थी। यह करीब एक महीने पहले की बात है। नोएडा सेक्टर-58 में सी-72 एक्सपोर्ट गारमेण्ट फैक्टरी है – सुमित इण्डिया प्रा.लि.। इस फैक्टरी में करीब 700 मजदूर काम करते हैं। मैं करीब तीन साल से यहां दिहाड़ी पर काम कर रहा था। 7-8 साल से काम कर रहे मजदूर बताते हैं कि यहां कभी किसी को परमानेण्ट नहीं किया गया। जिस दिन सिलाई मशीन की नीडिल की चुटकी गिरी, उसके दो दिन बाद जब मालिक को इसका पता चला तो उसने मुझे अपने चैम्बर में बुलवाया। उसने भद्दी गाली देते हुए पूछा कि, "तू शराब पीकर फैक्टरी आता है।" मैंने जब उसे बताया कि "साहब मैं तो शराब पीता ही नहीं"। तो उसने दो और गालियां देते हुए कहा कि "तब तू क्या अंधा है जो 1200 रुपये की नीडिल तोड़ दी, अब यह तेरी तनख्वाह में से कटेगा"। मालिक जिस तरीके से गाली-गलौज कर रहा था, वह मुझसे बर्दाशत नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि साहब, बात तो ठीक से करो। इस पर वह भड़क उठा और चीखने लगा "तू दो टके का आदमी मुझसे जबान लड़ाता है। अभी पुलिस को बुलाता हूं, जब 50 डंडे लगेंगे तेरे तो सारी चर्बी उतर जायेगी।"

इस कहा-सुनी के दस मिनट बाद मेरा हिसाब कर दिया गया। यहां का मालिक मज़दूरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। जब भी कोई मजदूर तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है या यहां तक कि सुपरवाइजर के साथ कोई बात हो जाती है, तो उसे इसी तरह गाली-गलौज कर या मार-पीटकर बाहर निकाल देता है। यहां यदि कोई मजदूर 5 मिनट लेट आता है तो उसकी आधे दिन की दिहाड़ी काट ली जाती है या गेट से वापस कर दिया जाता है। यदि कोई कुछ बोलता है तो हिसाब कर दिया जाता है। ऐसे हालात इसी फैक्टरी के नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है सभी कारखानों की यही स्थिति है। श्रम कानूनों की चर्चा करना ही बेमानी है। हर जगह मालिकों की जोर-जबर्दस्ती ही श्रम कानून है। ऐसे में क्या चुपचाप सब कुछ सहन कर जाना ही एकमात्र रास्ता है? मैं अपने साथ के मजदूर भाइयों को जानता हूं कि वे सब कुछ सहने के लिए वाकई में तैयार नहीं हैं। बल्कि वे सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन एक जगह जाकर ठहर जाते हैं कि अकेले क्या करें? एक बात मेरे दिमाग में उमड़ती-घुमड़ती है कि हम अकेले कैसे हैं? हम किसी भी फैक्टरी में मिल-जुलकर काम करते हैं। बिना एक-दूसरे की सहायता के कोई काम नहीं किया जा सकता है। हमारे ही दम पर लुटेरों की ये अट्टालिकाएं खड़ी हैं। मैं तो कहता हूं कि हमें इस अकेलेपन के अहसास को बदलना ही होगा। अपने बीच से ही लोगों को आगे आना होगा और एकजुट होना होगा। कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं दिखाई पड़ता।

आलिम अहमद नोएडा

गुजरातः फासीवादी भाजपा बेनकाब

गुजरात की घटनाओं ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि फासीवादी ताकतें धर्म के नाम पर किस तरह सुनियोजित बर्बर हत्याकाण्डों को अंजाम देती हैं। जिस तरह हिटलर के फासीवादी गुण्डों की फौज ने जर्मनी में यहूदियों का संगठित कत्लेआम किया था, गुजरात में विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार के तमाम संगठनों का नंगा नाच उससे कम नहीं था।

इन फासिस्टों का यह पुराना तरीका है। यहां मैं बस उस लोमहर्षक और भयानक साजिश का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका वर्णन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव राजेश्वर दयाल (आई सी एस) ने अपनी पुस्तक 'ए लाइफ आफ आवर टाइम्स' में किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1948 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों का कत्लेआम करने की साजिश रची थी। ऐन मौके पर आर.एस.एस. के ठिकानों पर मारे गये छापों में तमाम नक्शे और लोगों की सूचियां बरामद होने के बाद इस साजिश का भण्डाफोड़ हुआ। दयाल के मुताबिक सारी साजिश संगठन के सुप्रीमो गुरू गोलवलकर के निर्देशन और संचालन में सुनियोजित ढंग से रची गयी थी।

गुजरात भी इसी प्रकार के प्रायोजित हत्याकाण्ड का शिकार हुआ। तमाम अखबारों में छपी खबरों से यह बात साफ है। महीनों पहले से अल्पसंख्यकों के मकानों, दुकानों, कारखानों आदि की सूचियां तैयार की गयी थीं। दंगाइयों की भीड़ बाकायदा मतदाता सूचियां लेकर चल रही थी। घरों और इमारतों में आग लगाने के लिये हजारों की तादाद में रसोई गैस के सिलिण्डरों का इस्तेमाल किया गया। कई जगह भीड़ के साथ-साथ सिलिण्डरों से भरे ट्रक चल रहे थे। दुकानों के शटर और मकानों की ग्रिल काटने के लिए हत्यारों के पास गैस कटर जैसे औजार थे। विहिप और भाजपा के नेता मोबाइल फोन पर भीड़ को निर्देश दे रहे थे कि किसको कहां जाना है। गुजरात के एक अखबार ने तो कई महीने पहले एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि वह कौन सी दुकानें हैं जिनके नाम तो हिन्दू हैं पर मालिक मुसलमान। ऐसी दुकानों को छांट-छांटकर जलाया और लूटा गया। गुजरात पुलिस के कई अधिकारियों ने कहा कि दंगों के दौरान टेलीफोन पर गलत सूचनाएं देकर उनका ध्यान बंटाया जा रहा था। जाहिर है कि यह सब बिल्कुल सुनियोजित था। सवाल है कि कौन था इस योजना के पीछे? दंगों के दौरान बुलडोजर, रोडरोलर आदि का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसी भारी मशीनें कहां से आई इसके बारे में प्रशासन चुप बैठा है।

गुजरात के भूतपूर्व पुलिस प्रमुख के.एफ.रुस्तमजी का यह बयान गौरतलब है कि "मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि यदि जांच में यह बात पता चले कि पुलिस की निष्क्रियता का कारण ऊपरी आदेश था।" (13 मार्च, दैनिक भास्कर)

इससे हम समझ सकते हैं कि धार्मिक फासीवाद मानवीय मूल्यों के लिये किस तरह खतरा बन गया है। इसके मुकाबले के लिये हमें भगतसिंह का बताया रास्ता याद करना चाहिए। वह कहते हैं – "लोगों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है।... गरीब मेहनतकश जनता की भलाई इसी में है कि वह धर्म, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता और देश का भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाये और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करे। इससे एक दिन जनता की गुलामी की समस्त जंजीरें कट जायेंगी।" (जून, 1928 'किरती' में प्रकाशित)

अपने आपको भारतीय संस्कृति का एकमात्र संरक्षक एवं योग्य उत्तराधिकारी के रूप में प्रचारित करने वाले भाजपाई किस कदर अमानुषिक एवं बर्बर संस्कृति के पोषक हैं, यह बात लगातार साफ होती जा रही है।

'जनसत्ता' के अनुसार बर्दवान में कालाना थाना इलाके के कृष्णपुर गांव में एक परिवार के 18 लोगों का हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है। इस परिवार के एक बुजुर्ग की मौत पर उन्हें अग्नि नहीं देकर समाधि दी गई। यही वह भीषण अपराध है जिसकी सज़ा यह परिवार काट रहा है। और सजा देने वाले हैं भारतीय संस्कृति के ठेकेदार भाजपाई। आज इस परिवार के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ नहीं सकते, कोई शिक्षक उन्हें घर पर आकर पढ़ा नहीं सकता। घर का कोई सदस्य कहीं कामकाज अथवा नौकरी के लिये जा नहीं सकता। इस परिवार के साथ संबंध रखने वालों पर 501 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है और यह सारा तमाशा परम्परा के संरक्षण के नाम पर किया जा रहा है। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में इस किस्म की मध्ययुगीन बर्बरता को क्या सहन किया जाना चाहिए।

-तपीश मेंडोला, जयपुर

फासिस्टों को बेनकाब करना जरूरी है

'बिगुल' के मार्च'02 अंक में गुजरात में नरसंहार पर आपका सम्पादकीय लेख पढ़ा। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि "...भारत का वर्तमान हिन्दू कट्टरपंथी फासीवाद भी इस देश और पूरी दुनिया की वित्तीय पूंजी का ही एक चाकर है। यह हिटलर-मुसोलिनी की राजनीति की भारतीय रूप है। इसका पहला शत्रु मजदूर आन्दोलन है। अल्पसंख्यकों को लक्ष्य बनाकर यह उन्माद पैदा करता है, जन-एकजुटता को तोड़ता है और फिर मेहनतकशों की क्रान्तिकारी राजनीति को अपना निशाना बनाता है।" जरा एक दशक पहले की घटनाओं और वर्तमान घटनाओं पर गौर करें तो मंदिर-मस्जिद विवाद में एक बहुत बड़े षडयन्त्र की बू आती है। जब 1990 में नये किस्म की गुलामी की ओर ले जाने वाली नई आर्थिक नीतियां लागू हो रही थीं, डंकल ड्राफ्ट आ रहा था तो देश भर में धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें गुलामी का प्रतीक 'नई आर्थिक नीतियां' नहीं, बल्कि 'बाबरी मस्जिद' को बना दिया गया। इसके लिए रथयात्राएं निकालीं, धार्मिक उन्माद पैदा किया, दंगे कराये। 6 दिसम्बर 92 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और उसी लहर पर सवार सत्ता में भी जा पहुंचे। सत्ता में जाकर उन्होंने आर्थिक सुधारों की गति को बढ़ाकर तबाही-बरबादी मचाई। अमेरिका के आगे घुटने टेक दिये। अब जबकि दोहा में डब्ल्यू.टी.ओ. की बैठक में समर्पण कर आये हैं, एक खतरनाक जनविरोधी बजट पारित किया है और भयंकर दमनकारी पोटो लाया जा रहा है तो जन असंतोष को दबाने, जनता का ध्यान बंटाने के लिए गुजरात में नरसंहार करवा दिया। जरा देखिये, ये फासिस्ट कैसे जनता का ध्यान बंटाने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। इतनी मंहगाई है, बेरोजगारी है, लोग भूख से मर रहे हैं, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे जिन्दगी बिता रहे हैं, शिक्षा-स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा क्या, जीवन रक्षक दवाओं के अभाव में बच्चे मर रहे हैं। परन्तु उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मन्दिर है। अभी पिछले दिनों चार राज्यों के चुनाव हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसमें मुख्य मुद्दा पाकिस्तान विरोध बना दिया। पिछले कई सालों से देश की फासीवादी ताकतें लगातार ऐसा माहौल बना रही हैं कि जनता का ध्यान बंटा रहे, वह अपने मूल मुद्दों को किनारे कर इनके तमाशे में शामिल हो जाये, जिससे मेहनतकश जनता की बुनियादी हकों की लड़ाई रफ्तार न पकड़ सके। गुजरात की स्थितियां थोड़ी सामान्य होंगी और तब तक ये फासिस्ट कोई नया कांड कर देंगे। हालांकि जनता के बीच इनकी पोल धीरे-धीरे खुल रही है। इनको जितनी जल्दी हो, बेनकाब किया जाना जरूरी है। किसी भी तरह जनसंघर्षों की आग को तेज किया जाय, तभी ये अंधेरे के राक्षस भागेंगे।

राजेन्द्र आर्य 'आरोही', मेरठ

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियां

1. 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मजदूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मजदूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मजदूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मजदूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनबाजों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से क्रान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

बिगुल यहां से प्राप्त करें

♦ शहीद पुस्तकालय, डा. दूधनाथ, जनगण होम्यो सेवा सदन, **मर्यादपुर**, मऊ ♦ मौर्या बुक स्टाल, सआदतपुरा (निकट रोडवेज), मऊनाथभंजन, **मऊ** ♦ जनचेतना, जाफरा बाजार, **गोरखपुर** ♦ विजय इन्फारमेशन सेन्टर, कचहरी बस स्टेशन, **गोरखपुर** ♦ विश्वनाथ मिश्र, नेशनल पी.जी. कालेज, **बड़हलगंज**, गोरखपुर ♦ जनचेतना, डी 68, निरालानगर **लखनऊ** ♦ जनचेतना स्टाल, काफी हाउस के पास, हजरतगंज, **लखनऊ**, (शाम 5 से 8·30) ♦ राहुल फाउण्डेशन, 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, **लखनऊ** ♦ विमल कुमार, बुक स्टाल, निकट नीलगिरि काम्प्लेक्स, ए ब्लाक, इंदिरानगर, **लखनऊ** ♦ रामपाल सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास विकास, **रुद्रपुर** (ऊधमसिंहनगर) ♦ रवीन्द्र कुमार, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय, पन्तनगर ♦ प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, विश्वनाथ मंदिर गेट, बी.एच.यू. **वाराणसी** ♦ राजीव वर्मा स्टूडेण्ट एजुकेशनल सेंटर, मैनाताली (पुलिस चौकी के पास), मुगलसराय, जिला-चन्दौली ♦ राजेन्द्र प्रसाद, रेणु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, **रेणुकूट**, सोनभद्र ♦ सत्यम वर्मा, 81, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार-एक, **दिल्ली** ♦ ललित सती, एल.आई.सी., फैज रोड शाखा, **दिल्ली** ♦ नई किरण पुस्तक भंडार, एफ-56, हरकेश नगर, ओखला, नई दिल्ली ♦ डी. के. सचान, एस.एच.- 272, शास्त्रीनगर **गाजियाबाद** ♦ सुनील कुमार सिंह, सेक्टर-12 बी, 3159, बोकारो इस्पातनगर, **बोकारो** ♦ गणपतलाल, ग्राम काजी रसूलपुर, पो.-तेघड़ा, **बेगूसराय** ♦ पीपुल्स बुक हाउस, पटना कालेज के सामने, **पटना** ♦ समकालीन प्रकाशन (प्रा.) लि. पुस्तक बिक्री केन्द्र, आज़ाद मार्केट, पीरमुहानी, **पटना** ♦ विमर्श, 22, स्वास्तिक काम्प्लेक्स, रसल चौक ,जबलपुर ♦ नरभिन्दर सिंह, द्वारा डा. सुखदेव हुन्दल, ग्रा/पो. **सन्तनगर**, जिला-सिरसा ♦ पंकज, प्लाट नं. 33, सेक्टर-15, सोनीपत (हरियाणा) ♦ सुखविंदर द्वारा कॉ0 दशरथ लाल, मकान नं 14, लेबर कॉलोनी, गिल रोड, लुधियाना (पंजाब) ♦ राकेश गोरखा, सरस्वती पुस्तक मंदिर, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी, **दार्जीलिंग** ♦ बुक मार्क, 6, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, **कलकत्ता** ♦ शर्मा बुक स्टाल, थाना रोड, चराली, **तिनसुकिया** नेपाल ♦ विश्व नेपाली पुस्तक सदन, श्रवनपथ, बुटवल, रुपनदेई, **नेपाल** ♦ विशाल पुस्तक सदन, बिजुवार बाजार, प्यूठान राप्ती अंचल ♦ विशाल पुस्तक पसल, अस्पताल लाइन, बुटवल, **लुम्बिनी**, नेपाल ♦ लक्ष्मी नारायण मिश्र, 853, हिरनमगरी, सेक्टर 4, पूजानगर, **उदयपुर** (राज.)

व्यापक मेहनतकश एकता की दिशा में कंट्रोल्स ग्रुप के मजदूरों की पहल उम्मीद जगाती है

अजय

नोएडा। बिजली के उपकरण, खासकर स्विचगियर बनाने वाली कई इकाइयों की मालिक कम्पनी कण्ट्रोल्स ग्रुप्स के मजदूर मैनेजमेण्ट की धोखाधड़ी, वादाखिलाफी और प्रशासन के दलाल रवैये के कारण एक बार फिर आन्दोलन की राह पर उतरने के लिये मजबूर हुए हैं।

इस कम्पनी की चार इकाइयां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कासना में है जबकि ओखला में भी इसकी दो इकाइयां हैं। कम्पनी के मालिकान में से एक पूर्व न्यायमूर्ति पी.एन.खन्ना हैं जो मजदूरों के लिए साक्षात "अन्यायमूर्ति" बने हुए हैं।

1991 में यहां के मजदूरों ने अपने संघर्षों के दम पर तीन वर्षीय समझौता कबूलवाया था। मैनेजमेण्ट ने दो बार तो किसी तरह कांख-कूंखकर पैसे बढ़ा दिये लेकिन तीसरी बार मैनेजमेण्ट समझौते से साफ मुकर गया। इतना ही नहीं उसने झूठे आरोप लगाकर यूनियन के पदाधिकारियों समेत 17 लोगों को बर्खास्त कर दिया। यूनियन ने तीन वर्षीय समझौते को लागू करने तथा बर्खास्त मजदूरों को बिनाशर्त वापस लेने की मुख्य मांगों सहित 22 सूत्रीय मांगपत्रक मैनेजमेण्ट से लेकर उपश्रमायुक्त और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को दिया तथा बार-बार विभिन्न तरीकों से कागजी कार्रवाई और आन्दोलन के द्वारा उन्हें ध्यान दिलाता रहा लेकिन पांच साल के बाद भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

अब कण्ट्रोल ग्रुप के साथियों ने एक नई पहल लेते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जो उनके आंदोलन को मजबूत बनाने में तो मदद करेगा ही, भविष्य में नोएडा के मजदूर आंदोलन को भी एक नई दिशा दे सकता है। पहले तो यह कि चुनावबाज राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी ट्रेड यूनियनों के नेताओं के चंगुल में फंसे बिना उन्होंने अपनी कम्पनी की स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनायी। यह काम केवल एक फैक्टरी में ही नहीं हुआ बल्कि नोएडा सेक्टर 8 ए-7,8 एवं ए-22 में, कासना में और ग्रेटर नोएडा सी-58,59 में स्थित सभी इकाइयों के मजदूरों ने किया जो कि एक ग्रुप और एक ही मालिक की हैं। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने चारों इकाइयों की यूनियनों को मिलाकर 'कण्ट्रोल ग्रुप्स कर्मचारी संघ' नाम की फेडरेशन का गठन किया ताकि अलग-अलग लड़ने के बजाय एक ही मांग पर एक साथ लड़ा जा सके। फेडरेशन के गठन के बाद ही चारों इकाइयों में पिछले एक महीने से लंच और छुट्टी के समय मजदूर अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन बहरा गया मैनेजमेण्ट अभी सुगबुगाया भी नहीं है क्योंकि लेबर आफिस, लेबर कोर्ट और जिला प्रशासन की चुप्पी उसके लिए मीठी लोरी का काम कर रही है। लेकिन मजदूरों ने ठान लिया है कि वह इस कुम्भकरण को जगाकर रहेंगे।

कण्ट्रोल एण्ड स्विचगियर कम्पनी में संघर्षों का लम्बा इतिहास रहा है। 1977 तक पी.एन.खन्ना ने अपनी फैक्टरी में धन और प्रशासनिक बल पर न तो श्रम कानून लागू किया, न तो मजदूरों को संगठित होने दिया। फरवरी 1978 में मजदूरों ने श्रम सुविधाएं न मिलने के कारण संघर्ष किया, किन्तु सीटू नेतृत्व को मालिकों ने खरीद कर संघर्ष को कुचल डाला। संघर्ष से सबक लेकर धोखेबाज दलाल ट्रेड यूनियनों को किनारे कर सितम्बर 1981 में ओखला में मजदूरों ने कण्ट्रोल एण्ड स्विचगियर इम्प्लाइज एसोसियेशन बनाकर अपना हक हासिल करने के लिये संघर्ष किया और अपनी एकता के बल पर ई.एस.आई., पी.एफ., छुट्टी, बोनस, प्रतिमाह चाय भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, सालाना इन्क्रीमेंट, घर जाने का यात्रा भत्ता, बच्चों की पढ़ाई अलाउन्स, वर्दी आदि सुविधाएं हासिल कीं। इसमें से कई सुविधाएं कण्ट्रोल ग्रुप के नोएडा और कासना में काम कर रहे मजदूरों को भी मिल रही हैं। लेकिन अब देशी-विदेशी पूंजीपति लुटेरों की सेवा करने के लिए नंगई पर उतारू सरकार की शह पाकर बौराये मालिकान को यह सब देना भारी पड़ रहा है।

सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद मजदूरों के सामने यह बात साफ तौर पर जाहिर हो चुकी है कि पुलिस, प्रशासन, कोर्ट कचहरी देश के मजदूरों के लिये सिर्फ एक छलावा है। उनका असली मकसद पूंजीपतियों की लाठी बनकर मजदूरों के सिर पर बरसना ही है। इस बात का एहसास कण्ट्रोल्स ग्रुप ही नहीं पूरे नोएडा के मजदूरों को अच्छी तरह हो चुका हैं पूरा तंत्र किस तरह पूंजीपतियों की जेब में है इसके लिए सिर्फ एक उदाहरण काफी है। 3 फरवरी 2000 को उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह ने मजदूरों के दबाव में कम्पनी के निदेशक, उप श्रमायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश दिये थे। इन अधिकारियों ने यूनियन के अध्यक्ष किरणपाल को बुलाकर यह आश्वासन दिया कि फैक्टरी में काम शुरू हो जाने पर सब लोगों को बहाल कर दिया जायेगा। लेकिन उनका आश्वासन झूठा निकला और किसी को आज तक बहाल नहीं किया गया जबकि यूनियन ने मैनेजमेण्ट की सारी बातें मान लीं। बाद में अधिकारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तुम कानून का सहारा लो। मजबूर होकर यूनियन ने लेबर कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन तीन साल से लेबर कोर्ट में कोई जज ही नहीं बैठ रहा है।

यह साफ है कि कानूनी तौर तरीकों से मजदूरों कोइंसाफ मिलने की बची-खुची संभावना खत्म होती जा रही है और अब तो नये श्रम कानून लागू हो जाने के बाद मालिकान छुट्टा सांड़ की तरह घूमेंगे और मजदूरों के रहे-सहे जनवादी अधिकारों पर भी अंकुश लगा दिया जायेगा। यह कानून किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार द्वारा नहीं लाये जा रहे बल्कि पक्ष और विपक्ष की तमाम पार्टियों का खुला या गुपचुप समर्थन इनके पीछे है। दिखावे के लिए ही कुछ पार्टियां संसद के सुअरबाड़े में थोड़ी-बहुत चिल्ल-पों मचाती हैं ताकि कहीं अगले चुनाव तक जनता उन्हें भूल न जाये।

इसलिये अपने अधिकारों की हिफाजत मजदूरों को केवल अपनी एकजुटता और संघर्ष के बलबूते ही करनी है। इस दिशा में कण्ट्रोल्स ग्रुप के मजदूरों द्वारा अपनी फेडरेशन का गठन एक आगे का कदम है। आज जहां एक ही कारखाने के भीतर कई-कई यूनियनें मौजूद हैं वहां यह पहल एक नई दिशा देती है कि कम से कम एक मालिकान की विभिन्न फैक्टरियों के मजदूर तो एक हो रहे हैं। इसी तरह एक उद्योग के विभिन्न मजदूर और फिर एक क्षेत्र के तमाम कारखानों के मजदूर एकजुट होकर अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। यह बेहद जरूरी है क्योंकि आज मालिकान एकजुट हो रहे हैं और उनके साथ तो प्रशासन राजनीतिक पार्टियों, अखबार, टेलीविजन और धनिकों का पूरा वर्ग पहले से है लेकिन मजदूर बंटता ही जा रहा है। कण्ट्रोल ग्रुप के साथियों ने कैजुअल मजदूरों को परमानेण्ट करने की मांग उठाकर भी समझदारी का परिचय दिया है। हमें संगठित, असंगठित, कम्पनी के मजदूर, कैजुअल और ठेका के मजदूर जैसे भेद भुलाकर इस बात को याद करना होगा कि हम सब मेहनतकश हैं जो अपनी मेहनत को कौड़ियों के मोल पूंजीपतियों को बेचते हैं जो उसके दम पर करोड़ों-अरबों की कमाई करते हैं। जाति-धर्म-क्षेत्र जैसे हर तरह के बंटवारे

हापुड़ में बेगुनाह नौजवानों को पुलिस ने आतंकवादी बताकर पकड़ा और पोटो लगाया

(बिगुल प्रतिनिधि)

रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)। हापुड़ में जिन चार नौजवानों को स्पेशल टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस ने पिछले 23 मार्च को आतंकवादी बताकर पकड़ने का दावा किया था वे सीधे-सादे आम मुसलमान नौजवान निकले। ये सभी नौजवान रुद्रपुर जिले के अलग-अलग कस्बों के रहने वाले थे। पुलिस की इस झूठी कहानी का भाण्डा तब फूटा जब इस गिरफ्तारी के विरोध में रुद्रपुर के केलाखेड़ा कस्बे में हिन्दू-मुस्लिम सभी नागरिक सड़कों पर उतर आये।

हापुड़ में जिन चार नौजवानों को लश्कर-ए-तोइबा के आतंकवादियों को पनाह देने वाला बताकर गिरफ्तारी दिखायी गयी थी, उन्हें दरअसल 17 मार्च को ही रुद्रपुर के अलग-अलग स्थानों से पूछताछ के नाम पर पकड़ लिया गया था। ये चार नौजवान हैं – शमीम, रफीक (केलाखेड़ा), असलम (गदरपुर) और कल्लन खां (मजरासिला)। इनमें से गदरपुर निवासी असलम को बाद में पुलिस ने छोड़ दिया। बाकी तीनों का पोटो के तहत चालान कर दिया गया है और अब वे पुलिस रिमाण्ड पर हैं।

आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बनायी गयी स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) की अंधेरगर्दी का आलम यह है कि उसने रुद्रपुर के ही दो अन्य मुसलमान नौजवानों को आतंकवादी बताकर मुम्बई से भी 17 मार्च को पकड़ा है जिनका अभी तक कोई अता-पता नहीं है। ये दो नौजवान हैं – केलाखेड़ा निवासी रईस पुत्र अब्दुल मजीद और शकील पुत्र नजाकत अली। रईस ने 21 मार्च को स्वार (रामपुर) रहने वाली अपनी फूफी को अपने पकड़े जाने के बारे में फोन पर बताया था। ये दोनों नौजवान मुम्बई में छोटा-मोटा काम धन्धा कर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। इन पकड़े गये छहों नौजवानों को एक हफ्ते तक पुलिस ने कहां रखा था इसके बारे में पुलिस के आला अफसर बताने के लिए तैयार नहीं हैं। उधमसिंह नगर के एस.पी. ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि छापा तो पड़ा था लेकिन किस-किस को पकड़ा गया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

हापुड़ में आतंकवादियों को पकड़े जाने की खबरों पर लोगों ने विश्वास कर लिया होता अगर केलाखेड़ा में इसके खिलाफ जबर्दस्त प्रतिक्रिया की खबरें नहीं आतीं। तेईस मार्च को समूचा केलाखेड़ा बाजार बन्द रहा। सभी धर्मों और जातियों के लोग सड़कों पर उतर पड़े और जबर्दस्त प्रदर्शन किया। फर्जी मामले में फंसाये गये इन नौजवानों के परिवारवालों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रपति से भी इसकी शिकायत की है। जिस तरह इन बेगुनाह नौजवानों को आतंकवादी बताकर पकड़ा गया और उन पर पोटो ठोंक दिया गया उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि पोटो के पीछे भाजपा सरकार की मंशा क्या है। अभी तो यह शुरुआत है। जिस तरह 'टाडा' के तहत भारी संख्या अल्पसंख्यकों, जनतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं और क्रान्तिकारी जनान्दोलनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था उससे भी आगे बढ़कर पोटो का पाटा चलेगा, इसमें अब कोई शक नहीं रहना चाहिए। इसकी केवल एक ही काट है – पोटो के खिलाफ एक व्यापक जनान्दोलन तैयार करना। सभी मेहनतकशों एवं जनतांत्रिक अधिकार आन्दोलन से जुड़े लोगों को सड़कों पर उतरकर इसे चुनौती देनी होगी।

देवू कंपनी बीमार

साढ़े चार सौ मज़दूरों पर पड़ी छंटनी की मार

(बिगुल संवाददाता)

ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)। अमीरजादों के लिए सिएलो व मातिज कार बनाने वाली कोरियाई कम्पनी देवू मोटर्स ने 23 मार्च को 455 कर्मचारियों को निकाल बाहर किया। ग्रेटर नोएडा स्थित देवू के इस कारखाने से इन मजदूरों को लठैतों (सुरक्षा गार्डों) द्वारा गेट से खदेड़ दिया गया।

बताया जा रहा है कि यह कोरियाई कम्पनी पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। इसी बीच मोटर-गाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी मगरमच्छ 'जनरल मोटर्स' ने 'देवू' को सुझाव दिया कि "तुम हमसे ब्याह कर लो, हम तुम्हारी बीमारी दूर कर देंगे"। जानकार बताते हैं कि देवू ने 'जनरल मोटर्स' के "प्रेम निवेदन" को स्वीकार कर लिया है और उसने 'जनरल मोटर्स' के बताये नुस्खे के अनुसार मजदूरों के पेट पर लात मारनी शुरू कर दी है। जिन 455 मजदूरों को देवू ने धक्के देकर बाहर निकाला है, उन पर कामचोरी, अनुशासनहीनता और फर्जी प्रमाणपत्र के द्वारा नौकरी पा लेने के आरोप लगाये गये हैं। 455 मजदूरों की रोजी रोटी डकारकर हज को जाने वाली यह कोरियाई बिल्ली अब मजदूरों को अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ा रही है।

मुनाफे की हवस में पगलाई किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के बीमार पड़ने का मतलब होता है – मजदूरों की छंटनी और तालाबन्दी। मजदूरों का खून निचोड़कर अपनी तिजोरी भरने वाली ये कम्पनियां यदि पिछले वर्षों के मुकाबले में कम मुनाफा कमाती हैं तो

छाती पीटने लगती हैं कि हाय, हम तो तबाह हो गये। इनकी बीमारी दूर करने के लिए बलि का बकरा ढूंढा जाता है और मजदूर की गर्दन फिर पकड़ी जाती है। पूंजीवादी मीडिया बीमार कम्पनियों की तस्वीर ऐसे पेश करता है कि हमारे पढ़े-लिखे भलेमानुषों के मुंह से निकल पड़ता है "बेचारा मालिक!" जबकि कोई बीमार कम्पनी बिक भी जाये, तो उसका मालिक तबाह नहीं होता। वह उसका पैसा दूसरे कारोबार में लगाकर नये सिरे से नयी जगह पर मजदूरों की मेहनत को लूटना शुरू कर देता है। कम्पनी बिक जाने के बावजूद वह मालिक ढेर सारी विलायती दारू पी सकता है, इतनी ज्यादा कि कै कर दे और उसी में लोटपोट होकर गम गलत कर ले। देवू का यह कारखाना बिक भी जाये तो इसका मालिक, बड़े-बड़े मैनेजर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर मूंगफली बेचते नजर नहीं आएंगे। वे फिर भी अपने एअर कंडीशंड महलों में रहेंगे लूट की नयी साजिशें रचते हुए।

सवाल यह है कि छंटनीशुदा मजदूर कहां जायेंगे? देवू के कारखाने से निकाले गये मजदूरों ने नारेबाजी कर गुस्से का इजहार तो किया, लेकिन जालिम लुटेरों के खिलाफ लम्बी लड़ाई के लिए कमर कौन कसेगा? खासतौर पर आज के हालात में, जब हमारी "चुनी हुई सरकार" इन लुटेरों की पैरोकारी करते हुए श्रम कानूनों में "सुधार" कर रही है। पूंजीपतियों को छूट दे दी गई है कि मजदूर को जब चाहो काम पर रखो, जब चाहो निकाल बाहर करो यानी 'यूज एण्ड थ्रो'। देश भर के औद्योगिक केन्द्रों में छंटनी का दौर चल रहा है। ऐसे में, जबकि मेहनतकशों को मुनाफा पैदा करने वाली मशीनों में पेरने के लिए देशी-विदेशी धनपशु पर्दे के पीछे नापाक गठबंधन कर रहे हों, क्या यह सबसे पाक और जरूरी काम नहीं होगा कि देवू के मजदूर अपने बिरादरों के साथ व्यापक एकता का बंधन कायम कर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं।

बार्सिलोना में विश्व पूंजीवाद के मुंह पर कालिख पुती

पर फैसलाकुन शिकस्त के लिए विश्व सर्वहारा की सेना सजानी होगी

ललित

विश्व पूंजीवाद के मुंह पर कालिख पोतने का काम इस बार बार्सिलोना में हुआ। यह ठीक उस समय हुआ जब यूरोपीय संघ की बैठक चल रही थी, जहां पर लूट के माल के बंटवारे को लेकर समझौते हो रहे थे और नयी साजिशें रची जा रही थीं। स्पेन के बार्सिलोना शहर ने पहली बार इतने बड़े प्रदर्शन को देखा था। करीब तीन लाख लोग सड़कों पर पूंजीवाद विरोधी नारे लगा रहे थे, गीत गा रहे थे। 17 मार्च को हुए अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन में भाग लेने आ रहे हजारों लोगों को स्पेन-फ्रांस सीमा पर व अन्य जगहों पर रोक लिया गया था।

हालांकि यह एक शानदार प्रदर्शन था, लेकिन अभी इससे यह उम्मीदें नहीं पाली जानी चाहिए कि इसमें शामिल लोग साम्राज्यवाद की कब्र खोद ही डालेंगे। अलग-अलग कारणों से अलग-अलग वर्गों के लोग एकत्रित हुए थे और उन्होंने घोर मानवद्रोही व्यवस्था को एक चेतावनी दी। इससे पहले सिएटल और रियो में भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं। जिनमें विभिन्न देशों के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया है। इन प्रदर्शनों में जहां एक ओर जनवादपसन्द नागरिक, छात्र, बुद्धिजीवी शामिल होते रहे हैं तो दूसरी ओर रंग-बिरंगे एन.जी.ओ. ब्राण्ड 'आंदोलनकारी' भी इनमें बड़ी संख्या में सम्मिलित रहे हैं।

भाड़े के टट्टू और पूंजीवादी मीडिया आज विश्व पूंजीवाद को कितनी ही अजेय और अमर क्यों न सिद्ध करें, सच यह है कि आज साम्राज्यवाद असाध्य रोगों से ग्रस्त है और पूरी तरह इंसानियत के विरोध में जा खड़ा हुआ है। यह आये दिन एक के बाद एक विनाश की लीलाएं रच रहा है। भूमण्डलीकरण के विचारक भी इस बात को समझने लगे हैं कि बूढ़े, चालाक, नपुंसक पूंजीवाद की ऐयाशियों की पोल खुल चुकी है। तबाही-बर्बादी के समुद्र में धकेल दी गई मेहनतकश जनता स्वर्ग पर धावा बोलने के लिए कमर कस रही है। पूंजीवादी विचारक इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं कि आज भले ही सर्वहारा की सेना बिखरी हुई और कमजोर दिखाई पड़ रही हो, लेकिन यही वह ताकत है जो पूंजीवाद की कब्र खोदने के इरादे पर अटल है।

बार्सिलोना से पहले भी पूंजीवाद विरोधी बड़े प्रदर्शन हुए हैं और आगे भी होंगे। लेकिन यह तब तक साम्राज्यवाद के लिए खतरा नहीं बनेंगे, जब तक इन्हें एक सुनिश्चित प्रोग्राम पर वर्गीय दृष्टिकोण के साथ वर्गचेतन नेतृत्व के इर्द-गिर्द संगठित नहीं किया जायेगा। जब तक जन संघर्षों को एक मनके की माला में नहीं पिरोया जायेगा। इन प्रदर्शनों में बढ़चढ कर भागीदारी करने वाले एन.जी.ओ. ब्राण्ड जादूगरों को भी पहचानना होगा। इनके द्वारा उठाये जा रहे विरोध के मुद्दों की पड़ताल करें तो देख सकते हैं कि यह शालीन-कुलीन एन.जी.ओ. ब्राण्ड विरोध दरअसल छद्म विरोध है। यह वास्तविक विरोध के संगठित होने में एक बाधा है, उसके रास्ते की अड़चन है। यह जनता के बीच पल रहे साम्राज्यवाद विरोधी गुस्से के उफान को सेफ्टी वाल्ब के जरिये निकाल देता है। जब जनता सड़कों पर उतरती है, तो ये मुख्य मुद्दों से उसका ध्यान बांट देते हैं। ये रावण की नाभि के बजाय रावण के सिर को निशाना बनाते हैं। वास्तविक विरोध को विघटित कर नकली विरोध खड़ा करने वाले ये एन.जी.ओ. ब्राण्ड सूरमा दरअसल 'ट्रोजन हार्स' हैं। इनसे सावधान होने की जरूरत है। आज ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुधुवीयता की बात करते हैं, विकेन्द्रित संघर्षों का राग अलापते हैं। ऐसे लोग बार्सिलोना की सड़कों पर भी तख्तिया पकड़े थे और अपने देश में भी इनकी दुकानें देखी जा सकती हैं। इन बुद्धिमानों को यह बात समझ में नहीं आती कि बिना सेनापतित्व के, बिना एक कार्यक्रम के विश्व पूंजीवाद को टक्कर नहीं दी जा सकती। भूमण्डलीकरण के इस दौर में जब दुनिया भर के लुटेरे अपने तमाम अन्तरविरोधों के बावजूद सर्वहारा वर्ग पर एकजुट हमला बोल रहे हैं, तब विकेन्द्रित संघर्षों की बात करना पूंजीवाद विरोधी संघर्षों को कमजोर करना ही है।

बार्सिलोना की चर्चा करते हुए यदि हम अपने देश के हालात देखें तो एन.जी.ओ. ब्राण्ड छद्म संघर्षकारियों से लेकर बहुध्रुवीयता और विकेन्द्रित संघर्षों की गन्दगी फैलाने वाले कई बातबहादुर तमाम जनान्दोलनों में अपनी घुसपैठ कर रहे हैं। इनमें एन.जी.ओ. रूपी भिखमंगे तो अपने देशी-विदेशी आकाओं से फण्ड लेने के साथ-साथ "संघर्षों के कार्यक्रम" भी ले लेते हैं। इसके अलावा अलग-अलग मुद्दों को लेकर संघर्ष के नाम पर कदम ताल कर रहे आंदोलनकारी हैं, जो केवल स्थानीयतावाद के ही शिकार नहीं हैं, बल्कि विकेन्द्रित संघर्षों के शातिर वकील हैं। ये हिन्दुस्तान के मेहनतकश अवाम को कौन से मुक्ति के रास्ते पर ले जायेंगे, समझा जा सकता है।

बहरहाल, बार्सिलोना में हुए जबर्दस्त प्रदर्शन से यूरोपीय संघ भी चिंतित है। वह तीन लाख लोगों से उतना परेशान नहीं है। उसकी मुसीबत का कारण है ऐसे प्रदर्शनों में सर्वहारा वर्ग की भागीदारी।

आज भले ही मेहनतकश जनता के वर्ग सचेत मजदूर इन प्रदर्शनों में बहुत कम संख्या में हों, लेकिन यही वे "शैतान" हैं जो स्वर्ग पर धावा बोलने वालों के आगे-आगे चलेंगे, यही वह ताकत है जो लुटेरों के दिलों में आतंक पैदा करती हैं। यूरोपीय संघ ने मेहनतकश अवाम की संगठित ताकत से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है।

उसने ऐसे विरोध प्रदर्शनों को आतंकवाद के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। यानी अब आई.एम.एफ., वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू.टी.ओ., अमेरिका, यूरोपीय संघ आदि के खिलाफ प्रदर्शन करना आतंकवादी कार्रवाई माना जाय, इसकी तैयारी हो रही है। दुनिया भर में उठ रहे पूंजीवाद विरोधी संघर्ष और हर देश के पूंजीवादी शासक वर्ग का लगातार निरंकुश और दमनकारी होते जाना बता रहा है कि निकट भविष्य में बड़े तूफान आने वाले हैं। सवाल यह है कि उन तूफानों की अगवानी के लिए मेहनतकश अवाम की तैयारियां कैसी हैं।

नेपाली प्रधानमंत्री देउबा की भारत यात्रा

जनता के दमन में मदद का ठोस वादा लेकर लौटे

(बिगुल प्रतिनिधि)

दिल्ली। माननीय शेरबहादुर देउबा जी माह के तीसरे हफ्ते में भारत आये थे। उन्होंने यहां आकर अपनी समस्याओं से भारत के शासक वर्ग को अवगत कराया, चिंतायें साझा कीं, फोटो खिंचाई, शाबाशी को स्वीकारा, आश्वासन लिये, वायदे किये और प्रसन्नमुद्रा में वापस नेपाल चले गये। देउबा जी नेपाल के प्रधानमंत्री है, जहां की जनता पिछले चार माह से आपातकाल के काले दिनों को भुगत रही है, जहां इस इक्कीसवीं सदी में भी राजशाही के खात्मे और जनतंत्र की स्थापना के लिए आवाज उठाने पर जनता को भयंकर दमन का सामना करना पड़ रहा है।

नेपाली मेहनतकश जनता के बड़े हिस्से पर वहां के क्रान्तिकारियों, जिन्हें माओवादी कहा जाता है, का प्रभाव है। इन माओवादियों के आगे बढ़ते कदमों से वहां की राजशाही आतंकित है। भारत के पूंजीपति, जिनका नेपाल के बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा है, भी चिंतित हैं। इसके साथ ही अमेरिका भी नहीं चाहता कि नेपाल में कोई क्रान्तिकारी जन आंदोलन विकसित हो। यही वजह है भारत और अमेरिका के सत्ताधारी नेपाल के क्रान्तिकारी जन संघर्ष को कुचलने में नेपाल की राजशाही को मदद करने का इरादा व्यक्त कर चुके हैं। न्याय और सत्य के पक्ष में खड़ी नेपाली जनता के आंदोलन को बदनाम करने के लिए 'माओवादी आतंकवाद' का जुमला सुनियोजित तरीके से उछाला जा चुका है।

दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का ढोल पीटने वाले हमारे सत्ताधारी अपने पड़ोसी देश में जनतंत्र की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए किसी भी हद तक मदद करने को तैयार हैं, यह बात देउबा की भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट हो चुकी है। चर्चा है कि देउबा महोदय माओवादियों से निबटने की शिक्षा और भिक्षा लेने आये थे। देउबा भारत से जितना उत्साहित होकर वापस लौटे हैं, उससे तो यही लगता है कि नेपाल के शासक वर्ग और भारत के पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा का कोई गुरुमंत्र उन्हें मिल गया है।

नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा के दौरान भाजपा से लेकर माकपा तक के अनुभवी "जन सेवकों" से मुलाकात की। इसके साथ ही उनके साथ विशालकाय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अलग-अलग उद्योगपतियों से लेकर नौकरशाहों तक गहन विचार-विमर्श किया। लेकिन लगता है माओवाद का भूत उनका हर जगह पीछा करता रहा। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री ने देउबा को यथासंभव मदद का आश्वासन देकर राहत पहुंचाई। कितनी विडम्बना है कि सत्ता सुख भोग रही भाजपा सहित तमाम पार्टियों के नेताओं को नेपाल की जनता ने तब शरण दी थी, जब वे यहां के आपातकाल के डर से भागकर नेपाल गये थे। आज उसी नेपाली जनता के जनतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटने के लिए ये नेतागण रस्सी मुहैया करा रहे हैं। यही है शासक वर्गों का

(पेज 9 पर जारी)

पश्चिम बंगाल व राजस्थान सरकार के बजट

पक्ष-विपक्ष सब एक हैं, सब पूंजी के चाकर हैं

(कार्यालय प्रतिनिधि)

केन्द्र में बैठकर विपक्ष का स्वांग रचने वाली विपक्षी पार्टियों की असलियत क्या है, यह उनके द्वारा शासित राज्य सरकारों के बजट बखूबी बता देते हैं। पश्चिमी बंगाल में इस बार मार्च में पेश 2002-2003 के बजट पर पूंजीपतियों ने लाल पताका धारियों की पीठ थपथपायी है। बंगाल के उद्योगपतियों का कहना है कि इससे बेहतर बजट हो नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर, केन्द्र में विरोधी पक्ष की मुखियागिरी कर रही कांग्रेस ने राजस्थान में जो बजट पेश किया है, उसने 'अमीरों को पुचकार, गरीबों को दुत्कार' की कहानी दोहराई है।

बजट पर मिली शाबाशी से उत्साहित मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य 'मर्चेंट चैम्बर आफ कामर्स' के शताब्दी समारोह में अगले दिन पहुंचे और उद्योग जगत से अपील की कि वे बंगाल में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश करें और राज्य सरकार उनको सभी सुविधाएं मुहैया करायेगी। बुद्धदेव भट्टाचार्य मुनाफाखोरों के लाडले बने हुए हैं। आखिर क्यों न हों? वह गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चला सकते हैं, वह मजदूरों में पनप रहे असंतोष को देखते हुए चोर दरवाजे से आतंकवाद विरोधी कानून लाने की कोशिश में लगे हैं, उनकी सरकार लुटेरों के सरगना के भारत भ्रमण के दौरान विरोध कर रहे छात्रों-नौजवानों को जेल की सीखचों के पीछे कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि आम मेहनतकश जनता को भरमाने, उसके आंदोलनों को पथभ्रष्ट करने का काम संशोधनवादियों से बेहतर भला कौन कर सकता है। नकली वामपंथियों द्वारा की जा रही इस "महान सेवा" के लिए पूंजीपति वर्ग समय-समय पर आभार व्यक्त करे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

शासक वर्गों की सबसे विश्वसनीय पार्टी कांग्रेस ने राजस्थान में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसने आम गरीब की जिंदगी को और बदहाल बनाने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सर्वाधिक आपूर्ति घाटे वाले इस बजट द्वारा आटा, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कपड़े धोने का साबुन, मैदा, सूजी, बाहर से आने वाले खाद्य तेल, खल, तिलहन आदि महंगे हो जायेंगे। जबकि बजट में उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए कई रियायतों के प्रस्ताव किये गये हैं।

पश्चिम बंगाल की लाल चोंगाधारी नकली वामपंथियों की सरकार व पूंजीपति वर्ग की बूढ़ी वफादार सेविका कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार के बजट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों की आम दिशा पर इन चुनावबाज पार्टियों की आम सहमति है। संसद में बैठकर चुनावबाज जितनी भी बहसबाजी करें, विपक्ष में बैठकर गरीब के चूल्हे की चिन्ता का नाटक जितना करें लेकिन एक बात साफ है कि पूंजीवादी राजनीति की कलई अब खुल चुकी है, संसद के रास्ते इंकलाब लाने वालों का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। जनता इन बातफरोशों से उकता चुकी है। आम जन समझने लगा है कि इन चुनावबाज पार्टियों के बीच असली प्रतियोगिता यह है कि इनमें से कौन ज्यादा बेहतर तरीके से देशी-विदेशी लुटेरों के हितों को साध सकती है और जनतंत्र का मुखौटा भी बना रह सकता है। इन दोनों "कार्यभारों" में बेहतर संतुलन कायम रखना अब दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है और सत्ता का निरंकुश फासीवादी चेहरा सामने आता जा रहा है।

यह अकारण ही नहीं है कि भाजपा, जिसके फासीवाद का घिनौना रूप अभी गुजरात में कहर बरपा कर रहा है, आज साम्राज्यवाद और देशी पूंजीवाद की भक्त शिरोमणि साबित हो रही है और कांग्रेस को "रचनात्मक विपक्ष" की भूमिका में संतोष करना पड़ रहा है।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जिसे पूंजीवादी मीडिया छिपाता फिरता है। वह है – जनाक्रोश, जो सरकारों की जनविरोधी आर्थिक नीतियों और मजदूर विरोधी बजटों के खिलाफ लगातार पनप रहा है। बेरोजगारी, छंटनी, तालाबंदी, महंगाई की मार झेल रही मेहनतकश जनता के कुछ परिवार आज आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की 80 करोड़ जनता तो आत्महत्या नहीं कर लेगी। उसके असंतोष का लावा फूटेगा। तब बजट के पुलिन्दे ही नहीं, समूची पूंजीवादी व्यवस्था उसके निशाने पर होगी।

रपट

शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव के 71वें शहादत दिवस 23 मार्च के अवसर पर जन संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम

प्रभात फेरियां, नुक्कड़ सभाएं और मशाल जुलूस

(बिगुल प्रतिनिधि)

सोनीपत (हरियाणा) । शहीदे आजम भगत सिंह और उनके साथियों के अधूरे सपनों की याद दिलाने के लिए **नौजवान भारत सभा और दिशा छात्र संगठन ने 17 से 23 मार्च तक क्रान्तिकारी लोक स्वराज अभियान** चलाया। इसके तहत प्रभात फेरियों, नुक्कड़ सभाओं घर-घर जन सम्पर्क व पर्चा वितरण के माध्यम से अभियान के प्रचार दस्ते ने सोनीपत शहर की गलियों -मुहल्लों दफ्तरों में व्यापक आबादी के बीच जनता की सच्ची आजादी के लिए क्रान्तिकारी लोकस्वराज के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।

शहीदे आजम भगत सिंह ने कहा था कि **"जड़ता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए क्रान्तिकारी स्पिरिट पैदा करने की जरूरत होती है,...ताकि इन्सानियत की रूह में हरकत पैदा हो।"** इस अभियान के तहत प्रभात फेरियों का आयोजन जड़ता और निष्क्रियता में डूबे समाज में एक नयी हलचल पैदा करने के इसी उद्देश्य से किया गया था। भोर के झुटपुटे में जब अभियान के कार्यकर्ता क्रान्तिकारी समूह गान गाते हुए किसी मुहल्ले से गुजरते तो लोगों के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव होता था। प्रभात फेरियों के बाद घर-घर सम्पर्क और पर्चा वितरण के दौरान लोग भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के रास्ते और अभियान के उद्देश्य के बारे में बेहद उत्सुकता के साथ बातचीत करते थे।

अभियान के तहत शहर के देवनगर, विकास नगर, अशोक विहार, आदर्श नगर, ईदगाह कालोनी, एटलस कालोनी, लाल दरवाजा, आदि कालोनियों-मोहल्लों प्रभात फेरियों और घर-घर समपर्क के अलावा बस अड्डे, पी.डब्लू.डी. व नगर पालिका दफ्तर, कचहरी, सिंचाई विभाग के दफ्तर व कई नुक्कड़ों पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। इन नुक्कड़ सभाओं में लोगों ने काफी गौर से कार्यकर्ताओं की बातें सुनीं।

नुक्कड़ सभाओं और घर-घर सम्पर्क के दौरान अभियान टोली के कार्यकर्ताओं ने क्रान्तिकारी लोक स्वराज के नारे के अर्थ को विस्तार से समझाया कि उत्पादन, राजकाज और समाज के पूरे ढांचे पर मेहनतकश वर्ग का अधिकार कायम करने के लिए संघर्ष करना होगा। यानी मेहनतकशों की देशी-विदेशी पूंजी की लूट से पूरी आजादी और समाज के संचालन और नीतियां बनाने और फैसला लेने की ताकत मेहनतकशों के हाथों में। भगत सिंह का यही सपना था। वे और उनके साथी सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्यवाद से नहीं लड़ रहे थे वरन हर तरह के शोषण-उत्पीड़न का खात्मा कर एक बराबरी वाले समाज के लिए लड़ रहे थे।

नुक्कड़ सभाओं में कार्यकर्ताओं ने मन्दिर-मस्जिद के नाम पर खून-खराबा कराने वाली धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों के बाकावे में न आने का भी आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से कहा कि ये ताकतें इन मुद्दों को उठाकर रोजी-रोटी और पूंजी की लूटखसोट और भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं। और मेहनतकशों की एकता को तोड़ना चाहती है। उन्होने यह नारा दिया कि "जाति -धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो।"

एक सप्ताह तक चले इस अभियान का समापन 23 मार्च को शाम सात बजे मशाल जुलूस एवं संकल्प सभा के जरिये हुआ। लगभग 70-75 नौजवान बस अड्डे से हाथों में मशाल थामे और नारे लगाते शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरते हुए पुरखास अड्डे पंहुचे जहां संकल्प सभा हुई। सभा में नौजवानों ने भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। मशाल जुलूस में नौजवान **"भगत सिंह का सपना आज भी अधूरा, मेहनतकश और नौजवान उसे करेंगे पूरा", "भगत सिंह की बात सुनो, नयी क्रान्ति की राह चुनो", "खत्म करो पूंजी का राज, लड़ो बनाओ लोक स्वराज", "सारी सत्ता मेहनतकश को", "जड़ता तोड़ो आगे आओ लड़कर नया समाज बनाओ" आदि नारे लगा रहे थे।**

अभियान टोली में प्रमुख रूप से पंकज, परिमल, कश्मीर, सतबीर, कुलदीप, प्रवीण, यशपाल और अरविन्द शामिल थे।

लखनऊ

शहीदे आजम भगतसिंह की शहादत दिवस (23 मार्च) के अवसर पर स्थानीय अलीगंज (सेक्टर-क्यू एवं सेक्टर ESIB) में 'नौजवान भारत सभा' के कार्यकर्ताओं ने 'सामूहिक श्रमदान' का अयोजन किया। इसके तहत दो पार्कों में साफ-सफाई एवं वृक्षारोपण किया गया। जिसमें बड़े पैमाने पर नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं ने भाग लिया। 'श्रमदान' के पहले 'नौजवान भारत सभा' के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों का आह्वान किया कि आज जहां पौश इलाकों में सरकार की तरफ से साफ-सफाई, बिजली, पानी आदि की अतिरिक्त देखभाल की जाती है वहीं आम आदमी आज भी इन बुनियादी जरूरतों से महरूम है।

23 मार्च की सुबह प्रभात फेरी निकाली गयी। रात्रि को मशाल जुलूस निकाला गया। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सभा बहुत सफल रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले श्री जे.एन.सिंह एवं श्री गौड़ जी ने शहीदे आजम भगतसिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और इसके बाद नौजवान भारत सभा की टीम ने 'कारवां चलता रहेगा ....' गीत गाया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में 'नौजवान भारत सभा' के साथियों ने 'वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके', 'गर थाली आपकी खाली है तो सोचना होगा', रुके न जो, झुके न जो', 'एक हैं हमारी आज राहें', 'मिल के चलो, मिल के चलो' आदि क्रान्तिकारी गीत गाये। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने भी 'क्रान्ति के लिए उठे कदम', 'तू जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत में यकीन कर' आदि गीतों की प्रस्तुति की। नौजवान भारत सभा की तरफ से नुक्कड़ नाटक 'देश को आगे बढ़ाओ' भी किया गया जिसके द्वारा पतनशील पूंजीवादी राजनीति को बेनकाब किया गया।

सभा में अपनी बात रखते हुए 'नौजवान भारत सभा' के साथी देवेन्द्र ने कहा आज जब शासक वर्ग क्रान्तिकारियों की स्मृतियों को मिटाने की हरचन्द कोशिशों में लगा है तो ऐसे में शहीदे आजम भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव एवं क्रान्तिकारी कवि पाश को याद करना और भी जरूरी है।

श्री आर.एन.मिश्रा जी ने कहा कि आजादी के 55 सालों बाद भी हम सही मायने में आजाद नहीं हैं यह आजादी पूंजीपतियों की है। हमें अधूरी आजादी मिली है। अतः क्रान्तिकारियों के सपनों के भारत के निर्माण के लिए एक नयी क्रान्ति की तैयारी करनी होगी।

नौजवान भारत सभा के साथी राकेश ने कहा कि भगतसिंह ने कहा था – आज जब सारी चुनावबाज पार्टियां पूंजीपतियों के लिए नीतियां बना रही हैं, फैक्टरियों में छंटनी, तालाबंदी हो रही है, शिक्षा को बिकाऊ माल बनाया जा रहा है और जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है जिसकी वजह से पोटो जैसे कानून आ रहे हैं तब भगतसिंह की अधूरी लड़ाई को और तेज कर देना होगा। यही एकमात्र रास्ता है।

श्री जे.एन.सिंह ने कहा आज नौजवानों के अलावा प्रत्येक संवेदनशील नागरिक को भगतसिंह के विचारों को आगे ले जाना होगा।

सभा में मुख रूप से नरेन्द्र सिंह, तारिक जी, इमरान, आर.सी. श्रीवास्तव, अफजाल, फरकत लखीमपुरी, संतोष, अतुल, जाय मुखर्जी, मोहित, दुर्गेश, अमित, भूपेन्द्र, अजय, विनय आदि ने शिरकत की।

आयोजन स्थल पर पुस्तक एवं पोस्टर प्रदर्शनी भी लगायी गयी जिसे स्थानीय लोगों ने देखा और सराहा।

गोरखपुर,

"छंटनी, तालाबन्दी व निजीकरण की नीतियों के लागू हुए एक दशक बीत चुके हैं और उसके नतीजे में आम मेहनतकश जनता को मिला है – महंगाई, वी.आर.एस., बेरोजगारी व जीवन की बुनियादी जरूरतों से महरूम होते जाना। दरअसल ये नीतियां हैं ही बड़े-बड़े कारपोरेटों, पूंजीपतियों व बड़े नौकरशाहों की तिजोरियां भरने के लिए और इसके लिए यह व्यवस्था आम मेहनतकशों के रक्त मज्जा को निचोड़ रही हैं। आम जनता के खिलाफ आज यह मुट्ठी भर तबका अपने लूट के स्वर्ग को बचाने के लिए जंग लड़ रहा है।" उपरोक्त बातें दिशा छात्र संगठन के आदेश सिंह ने नौजवान भारत सभा व दिशा छात्र संगठन द्वारा आयोजित शहीदे आजम भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव व अवतार सिंह 'पाश' और गणेश शंकर विद्यार्थी के शहादत के अवसर पर आयोजित सभाओं को सम्बोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि, "हम यह कहना चाहते हैं कि यह युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति – भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज शासक या सर्वथा भारतीय ही हों, और यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और सृष्टि में एक नये युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। शहीदे आजम भगतसिंह के उक्त विचार को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि भगतसिंह के इन विचारों को आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़कर पहलकदमी लेनी होगी, अपने क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण करना होगा और सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है।

इस अवसर पर सुबह बेतियाहाता चौराहे पर स्थित शहीदे आजम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। और आवास विकास कालोनी, शाहपुर के लक्ष्मीबाई पार्क के पास शहीदों के चित्रों व विचारों के उद्धरणों की पोस्टर प्रदर्शनी लगायी गयी। दिशा व नारी सभा की सांस्कृतिक टोली ने क्रान्तिकारी गीतों की प्रस्तुति की। 23 मार्च से 26 मार्च तक इस अवसर पर निकाले गये 'एक सपने को टालते रहने से क्या होता है?' नामक पर्चे का मुहल्ले कालोनियों में वितरण किया गया।

मर्यादपुर, मऊ। "विगत एक दशक से चल रही निजीकरण की नीतियां अब आम जनता की तबाही-बर्बादी के निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। खेती के अनाज के भण्डारण की सीमा को समाप्त करके, अनाजों के व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाकर और यूरिया खाद की सब्सिडी हटाकर – सरकार ने 90 फीसदी मझोले व छोटे किसानों और खेत मजदूरों की आबादी को सड़कों पर धकेल दिये जाने का मुकम्मिल इंतजाम कर दिया है।" उपरोक्त बातें नौजवान भारत सभा के डा. जसवन्त ने शहीदे आजम भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव और 25 मार्च गणेश शंकर विद्यार्थी के शहादत दिवस पर आयोजित विभिन्न सभाओं को सम्बोधित करते हुए कही।

डा. जसवन्त ने मधुबन में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि, आज जनद्रोही हो चुकी यह व्यवस्था मुट्ठी भर देशी-विदेशी घरानों की थैलियों को मोटी करने के लिए मजदूरों-किसानों को अपनी जगहों-जमीन से उजाड़कर (खाद्य प्रसंस्करण की) तीसरी क्रान्ति करने जा रही है। कहने को तो यह आम किसानों के भले के लिए है लेकिन वास्तविकता यह है कि, यह मुट्ठी भर बड़े किसानों, फार्मरों-कुलकों और साहूकारों का ही भला करेगी बाकी जनता के लिये तो यह तबाही ही तबाही है। उन्होंने शहीदे आजम भगतसिंह की इन पंक्तियों, "अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित करे या पूरा न कर सके तो नौजवानों का अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि वह ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके या तबाह कर दे।" का उल्लेख करते हुए आम जनता व नौजवानों का आह्वान किया कि अब हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा और खुद ही अपने संगठनों का निर्माण करना होगा।

मर्यादपुर में आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुए देहाती मजदूर-किसान यूनियन के डा. दूधनाथ ने कहा कि, आज जब जनता अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही है तब यह जनद्रोही व्यवस्था और उसके मुखौटे राजनीतिक दल जाति व धर्म-क्षेत्र के नाम पर आम मेहनतकश जनता के बीच भेद डाल रहे हैं। धर्म के नाम पर दंगे करा रहे हैं। जबकि संसद में बैठकर सभी पोटो व श्रम कानूनों में परिवर्तन कर मजदूरों-किसानों के हकों पर ताला लगा रहे हैं। उन्होंने आम जनता को आगाह करते हुए कहा कि हमें ऐसी शक्तियों से चौकस रहना होगा और शहीदों के बताये रास्ते पर चलते हुए, शहीदों के सपनों को साकार करना होगा।

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम भेड़िया में आयोजित सभा से हुई, नौजवान भारत सभा व देहाती मजदूर किसान यूनियन ने संयुक्त रूप से मर्यादपुर से मधुबन तक साइकिल जुलूस निकाला, पर्चा वितरित किया व फतेहपुर तालरतोय, कठघरा शंकर व अन्य जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को आयोजित किया। सभाओं में नन्दलाल, अजय प्रकाश व नन्हेलाल ने भी अपनी बात रखी।

(पेज 1 से आगे)

होण्डा पावर प्रोडक्ट कारखाने में अवैध तालाबंदी...

फार डेमोक्रेटिक राइट्स' (पी.यू.डी.आर.) की तीन सदस्यीय टीम ने भी होण्डा कारखाने का दौरा किया और यूनियन एवं मैनेजमेण्ट के अतिरिक्त डी.एम. और श्रमायुक्त से भी बातचीत की। उनकी रिपोर्ट भी एक-दो दिन के भीतर ही आ जायेगी। इस बीच दिल्ली, लखनऊ, नोएडा आदि स्थानों से लगातार मजदूर यूनियनों और जनसंगठनों की ओर से उत्तरांचल सरकार और स्थानीय प्रशासन को फैक्स संदेश और तार भेजकर होण्डा मजदूरों को सड़क पर धकेलने की साजिश का पुरजोर विरोध लगातार जारी है।

शिफ्टिंग की साजिशाना तैयारियां काफी पहले से जारी थीं

पोर्टेबल जनरेटर व पम्पसेट बनाने वाली इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी का मैनेजमेण्ट पिछले लगभग एक साल से कारखाने की शिफ्टिंग की योजना पर काम कर रहा है। पहले कुछ विभागों की शिफ्टिंग फिर पूरे कारखाने की शिफ्टिंग की योजना है। लेकिन 'श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन' की अगुवाई में मजदूरों के लगातार प्रतिरोध के कारण अब तक यह योजना कामयाब नहीं होने पायी। इसीलिए एक शातिराना चाल के साथ मैनेजमेण्ट ने मजदूरों पर फैसलाकुन चोट करने का फैसला लिया।

पिछले 25 फरवरी को मैनेजमेण्ट ने बाहर से कुछ क्रेनों और फोर्क लिफ्टों को मंगाया और आनन-फानन में कारखाने की एल्युमिनियम शाप की मशीनें खोलना शुरू करवा दिया। मजदूरों ने इसका जमकर प्रतिरोध किया। मजदूरों ने तुरत-फुरत एकजुट होकर लिफ्टों आदि को न केवल भीतर घुसने से रोक दिया वरन उसे इलाके से बाहर खदेड दिया। उधर कारखाने के भीतर भी मजदूरों ने मशीनों को खोलने से रोक दिया। फिर उन्होंने अपनी शिफ्ट ड्यूटी करने के साथ ही चौबीसों घण्टे गेट पर रुककर चौकसी शुरू कर दी। इस बीच मैनेजमेण्ट सभी दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की 'ब्रेक' लगा चुका था।

26 फरवरी को कारखाना मैनेजरों ने मशीनों को खोलने की गरज से एल्युमिनियम शाप में काम करने वाले सभी मजदूरों का दूसरे विभागों में ट्रांसफर कर विवादित विभाग में अघोषित तालाबन्दी कर दी। लेकिन मजदूरों ने दूसरे विभागों में जाने से इनकार कर दिया। वे एल्युमिनियम शाप में ही बने रहे और मशीनें नहीं खोलने दीं। इस पर खिसियाए मैनेजरों ने मजदूरों और उनके प्रतिनिधियों को धमकियां देना शुरू कर दिया। हालत धीरे-धीरे और बिगड़ती गयी। 5 मार्च को मैनेजमेण्ट ने गार्डों के भेस में 70-80 अराजक तत्वों को भर्ती कर लिया। 6 मार्च को रात की पाली में मजदूरों को ड्यूटी पर न रखकर आफिसर/स्टाफ रखे गये और विवादित मशीनें खोलना शुरू कर दिया।

अपनी चाल आगे बढ़ाते हुए मैनेजमेण्ट ने अगले दिन 7 मार्च की सुबह विवादित विभाग के सभी 32 मजदूरों को (बाद में एक और, कुल 33) को कार्यमुक्त कर दिया। इसका विरोध करने पर सभी मजदूरों के लिए गेट बन्द कर पूरे कारखाने में गैरकानूनी तालाबन्दी कर दी गयी। तब से सभी मजदूर कारखाना गेट पर धरने पर बैठे हैं। मैनेजमेण्ट ने इसी दिन परिवहन सेवा भी बन्द कर दिया।

मैनेजमेण्ट काफी योजनाबद्ध ढंग से अपनी कार्रवाइयां कर रहा था। उसने गुपचुप ढंग से पहले ही कारखाने में हड़ताल व तालाबन्दी पर छह माह के लिए रोक का शासनादेश हासिल कर लिया था। वह मजदूरों पर हड़ताल थोपकर उलझाने की कोशिश में था। लेकिन यूनियन भी सचेत थी। उसने समय पर कारगर कदम उठाते हुए विभागीय तालाबन्दी और पूर्ण तालाबन्दी का मुद्दा उठाते हुए शासन-प्रशासन-श्रम विभाग को कई पत्र भेजे। अपने ही जाल में उलझ जाने के बाद मैनेजमेण्ट ने फिर एक नयी चाल चली। उसने श्रमायुक्त (डी.एल.सी.) के सामने सभी मजदूरों को काम पर लेने का वायदा किया और अगले दिन (8 मार्च) सुबह मजदूरों से एक वाहियात अण्डरटेकिंग (घोषणापत्र) भरवाने की असफल कोशिश की। इस घोषणापत्र के तहत हर मजदूर खुद को गैरकानूनी हड़ताल का दोषी मानकर यह घोषित करता कि वह शिफ्टिंग में मैनेजमेण्ट की मदद करेगा और निकाले गये मजदूरों के बारे में कोई सवाल नहीं उठायेगा। ऐसा होने पर उसकी नौकरी अपने आप खत्म हो जायेगी।

मैनेजमेण्ट जब इस चाल में भी कामयाब न हो सका तो उसने तमाम दूसरे हथकण्डों से मजदूरों को प्रताड़ित करना शुरू किया। उसने तमाम मजदूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाने के साथ ही आवश्यक सेवा के बहाने पावर हाउस के चार मजदूरों को भी निकाल बाहर किया।

इधर मजदूरों के संगठन ने पूरी घटना और प्रबन्धकों की साजिश का भाण्डा फोड़ते हुए उत्तरांचल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, श्रमायुक्त से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार सहित जिला प्रशासन को अनेक पत्र/ज्ञापन भेजे। साथ ही अपने आन्दोलन को भी तेज करना शुरू कर दिया।

होण्डा-मजदूरों के संघर्ष में व्यापक मजदूर आबादी शामिल

संयुक्त मजदूर संघर्ष मोर्चा की पहल पर इलाके की लगभग दो दर्जन यूनियनों-संगठनों ने मिलकर **होण्डा बचाओ संघर्ष समिति** का गठन किया और आन्दोलन की बागडोर उसे सौंपी। इसी क्रम में 18 मार्च को उपश्रमायुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में स्त्रियों-बच्चों सहित सैकड़ों मजदूरों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया और उपश्रमायुक्त का दिन भर घेराव किया। उस दिन त्रिपक्षीय वार्ता भी थी जो बेनतीजा समाप्त हो गयी। इन प्रदर्शनकारियों की पुलिस से काफी तीखी झड़पें भी हुईं।

आन्दोलन की अगली कड़ी में 22 मार्च को भी होण्डा गेट पर भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। **नारी सभा** के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने डेढ़ घण्टे तक गेट जाम रखकर मैनेजरों को गेट से बाहर नहीं निकलने दिया। 23 मार्च को शहीदे आजम भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव का शहादत दिवस धरना स्थल पर ही मनाया गया। होलिका दहन और होली का कार्यक्रम भी गेट पर ही मनाया।

होण्डा मजदूरों के इस न्यायपूर्ण आन्दोलन में न केवल पूरे इलाके की यूनियनों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों व आम जनता का भरपूर सहयोग व समर्थन मिल रहा है वरन पूरे उत्तरांचल राज्य, पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों से समर्थन में शासन-प्रशासन को पत्र/ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। दिल्ली में कारखाने के मुख्य कार्यालय पर कई यूनियनों-संगठनों के प्रतिनिधि प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपने गये जिसे लेने से उसने इनकार कर दिया। इन सभी कार्रवाइयों से बौखलाए होण्डा मैनेमण्ट ने अब नयी चालें चलना शुरू कर दिया है। उसने होण्डा मजदूरों में से गद्दारों को तलाशने और आन्दोलन को तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वह तरह-तरह से अफवाहें फैलवाने और भितरघात के असफल प्रयास में लगा है। लेकिन होण्डा के सचेत मजदूर और ज्यादा मजबूत होते हुए इन कुत्सित चालों का पर्दाफाश करने में मुस्तैदी से जुट गये हैं।

दरअसल होण्डा कारखाने की शिफ्टिंग से यहां से सीधे जुड़े महज 1005 परिवारों का ही भविष्य नहीं जुड़ा है। बल्कि प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से जुड़े, यहां सामान ढोने वालों से लेकर मकान मालिकों व पूरे बाजार तक पर, कुल मिलाकर पूरे राज्य के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही, चूंकि यहां का श्रमिक संगठन न केवल कैजुअल-परमानेण्ट के भेदभाव को मिटाकर एक जुझारू संगठन के रूप में जाना जाता है, वरन पूरे इलाके के किसी न्यायपूर्ण संघर्ष में अपनी वर्गीय पक्षधरता के साथ शिरकत करने के कारण क्षेत्र के मजदूर आन्दोलन के एक महत्वपूर्ण स्तम्भ के तौर पर भी जाना जाता है। इस कारण होण्डा प्रबन्धन व पूरे राज्य के पूंजीपतियों के चैम्बर की आंखों में भी यह संगठन खटकता रहता है। इसलिए इस आन्दोलन का भविष्य पूरे इलाके के मजदूर आन्दोलन के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

शिफ्टिंग क्यों? – जापानी साम्राज्यवादी डाकुओं का सरगना होण्डा आखिर चाहता क्या है?

इस शिफ्टिंग के पीछे की एक खास वजह तो यह है कि एक तो प्रबन्ध न इस क्षेत्र से सरकारी सब्सिडियां और सहूलियतें खा चुका है और नयी जगह खाने के फिराक में है। दूसरे जापानियों का यह फण्डा है कि पूरे असेम्बली लाइन को बिखेर दिया जाए ताकि संगठित मजदूर आबादी एक साथ न रह सके। तीसरे यहां के श्रमिकों को कुछ बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आज लुटेरे मालिकान मामूली दिहाड़ी पर और कैजुअल मंजदूरों से ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं। 'हायर एण्ड फायर' का तरीका लागू करना चाहते हैं। अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जापानी प्रबंधकों ने किश्तों में फैक्टरी शिफ्टिंग की योजना बनाई। पहले उन्होंने असेम्बली, पेण्ट, वेल्ड, अल्टरनेटर आदि के ढेरों काम यहां से बाहर ठेके पर भेजा। अब एल्युमिनियम शाप के साथ-साथ दूसरे विभागों – टूल रूम, मैन्टेनेन्स, स्टोर, आउट प्लांट क्वालिटी, स्पेयर पार्ट्स, आउट प्लांट सी के डी (पैकिंग) व रोटर शाफ्ट का भी ज्यादातर काम यहां से चला जाएगा। अन्त में इस खोखले कारखाने से मजदूरों को निकालना व इसे बन्द करना आसान हो जाएगा। वास्तव में, होण्डा मजदूरों के सामने मौजूदा संकट की शुरुआत उस वक्त से हुई जब यह कारखाना पूरी तरह जापानियों के कब्जे में आ गया। 1985 में स्थापित और 1987 से उत्पादन करने वाला यह कारखाना भारतीय पूंजीपति श्रीराम और जापानी समूह होण्डा के साथ 'श्रीराम होण्डा पावर इक्यूपमेण्ट लि.' नाम का संयुक्त उपक्रम था। शुरू में 5-10 करोड़ रुपये घाटे वाला यह कारखाना धीरे-धीरे 25-26 करोड़ रुपये वार्षिक फायदे में चला गया। 1998 तक श्रीराम ग्रुप अपने पूरे मुनाफों के साथ इससे बाहर हो गया और यह जापानियों के हाथ में चला गया। चूंकि इस बीच यहां श्रमिक संगठन भी और मजबूत व वर्ग सचेत हो चुका था इसलिए जापानियों ने शिफ्टिंग की योजना पर काम करना शुरू किया। इसके तहत उसने पहले कैजुअल-परमानेण्ट के बीच बंटवारा पैदा करने की कोशिश की, पहाड़-मैदान का विवाद खड़ा करना चाहा। फिर संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह रावत और एक दूसरे मजदूर साथी राजकुमार कठैत को झूठे आरोपों में बाहर किया। वर्तमान पदाधिकारियों पर झूठे आरोप मढे। पूर्व मंत्री बी.सी. पाण्डे को फर्जी आरोप पत्र दिये। इन सबसे जब वह पूरी तरह कामयाब न हो सका तो उसने उग्र तेवर में यह हमला बोला है।

लेकिन होण्डा मजदूर इन सबसे सचेत अपने संघर्षों को धारदार बनाते रहे। अब वे इसे इलाकाई जनान्दोलन बनाने के प्रयास में लग गये हैं। 'नारी सभा' के प्रयास से महिलाओं की भागीदारी से आन्दोलन में और भी गति आ गई है। होण्डा मजदूर आज उदारीकरण के दौर की मजदूर विरोधी नीतियों, देशी पूंजीपतियों और विश्व साम्राज्यवादी ताकतों के संयुक्त हमलों और सरकार के हमलावर तेवर को भी अच्छी तरह देखते समझते रहे हैं। शासन-प्रशासन को तमाम खतो-किताबत के बाद भी उसकी ओर से कोई पहल न लेने को भी समझ रहे हैं। वे श्रम विभाग की मध्यस्थता में असफल वार्ताओं की नौटंकी को भी देख रहे हैं। न्यायालय द्वारा तमाम तर्कों के बावजूद कारखाना परिक्षेत्र से 200 मीटर में धरना-प्रदर्शन पर रोक के स्थगनादेश को भी समझ रहे हैं। उनके लिए यह और साफ हो रहा है कि शासन-प्रशासन-पुलिस- न्यायालय सब पूंजीपतियों की सेवा में आज और नंगई से खड़े हैं। उनके लिए यह भी साफ होना कोई मुश्किल नहीं है कि सरकारें पूंजीपतियों की मैनेजिंग कमेटी हैं। और यह कि यह दौर छंटनी-तालाबन्दी का दौर है, श्रम कानूनों में घातक परिवर्तनों का दौर है। साथ ही यह मजदूर आन्दोलन के बिखराव का भी दौर है। ऐसे संकट के दौर में यह संघर्ष चल रहा है। इसीलिए इस आन्दोलन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने-समझने की जरूरत है। किसी भी भ्रम व भटकावों से दूर खड़े होकर इसे इलाके के मजदूरों के एक व्यापक आन्दोलन के रूप में फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। होण्डा मजदूर अब इसके लिए जुट गये हैं।

(पेज 1 से आगे)

आतंकवाद विरोधी कानून पारित...

और कुछ कर भी नहीं सकता। मुनाफे और बाजार की जिस अर्थव्यवस्था का वह मालिक है उसका संकट दूर करने का उसके सामने एक ही रास्ता है – मेहनतकशों के खून की एक-एक बूंद निचोड़कर सिक्कों में ढाले दो। निजीकरण-उदारीकरण, श्रम कानूनों में बदलाव उसकी इन्हीं जरूरतों की देन है। बाजार और मुनाफे की अर्थव्यवस्था का तर्क उसे खींचकर यहां लाया है। इससे वह पीछे नहीं हट सकता। यह शासक वर्ग जानता है।

इसी तरह शासक वर्ग यह भी जानता है कि तबाह-बरबाद हो रहे लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। इतना इतिहास उसे पता है। वह वर्तमान में अपना भविष्य भी देख रहा है।

देश के भीतर और दुनिया भर में जनता सड़कों पर उतर रही है। दुनिया एक जबर्दस्त उथल-पुथल की ओर बढ़ती जा रही है, इसका संकेत उसे मिल चुका है।

भविष्य के इसी खतरे से निपटने की तैयारी में पूरी दुनिया के लुटेरे हुक्मरानों को पोटो जैसे कानूनों की जरूरत है। इसीलिए, भारत ही नहीं दुनिया भर में हुक्मरान पोटो जैसे कानून बना रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन में भी ऐसे ही कानून बनाये जा चुके हैं। इसीलिए पूंजीवादी लुटेरों के सरगना अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भारत की संसद द्वारा आतंकवाद निरोधक कानून पास करने का स्वागत किया है।

मतलब यह कि शासक पूंजीपति वर्गों को आज दमन की पूरी मशीनरी को चाक-चौबन्द करने की जरूरत है। ऐसे में उनके भाड़े के टट्टुओं – तमाम चुनावी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को अपने आकाओं की मर्जी पूरी करनी ही है।

आज जो विपक्ष में है अगर वे सरकार में होते तो वे भी पोटो लाते और शायद भाजपा विरोध में खड़ी होती, जैसे उसने 'टाडा' का विरोध किया था।

आतंकवाद निरोधक कानून किसके खिलाफ लागू होगा, इस पर अब भी अगर किसी को भ्रम हो तो गुजरात में पोटो के इस्तेमाल का उदाहरण देख लेना चाहिए। गोधरा काण्ड के दोषियों के खिलाफ नरेन्द्र मोदी ने जिस तत्परता के साथ पोटो लगाया था उससे क्या सरकार की मंशा का पता नहीं चलता? गोधरा काण्ड के बाद गुजरात में जिस तरह सरकारी संरक्षण में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसके दोषियों पर पोटो लगाने की बात तो दूर, उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिये जा रहे हैं। भले ही फौरी दबाव में गुजरात में मुसलमानों पर लगा पोटो वापस ले लिया गया है लेकिन सरकार ने इरादे का इजहार कर दिया है।

आतंकवाद तो सिर्फ बहाना है, पोटा के निशाने पर जनता है। इसका इस्तेमाल होगा जनान्दोलनों के खिलाफ – अल्पसंख्यकों, दलितों और समाज के शोषित-उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ। इसलिए यह बहस बेमानी है कि पोटा का गलत इस्तेमाल होगा या नहीं, इसे लाया ही गया है बदनीयती के साथ और गलत इस्तेमाल करने के लिए ही।आतंकवाद निरोधक कानून के प्रावधान कितने खतरनाक हैं, इसके बारे में हम 'बिगुल' के पिछले अंकों में काफी विस्तार से दे चुके हैं। आतंकवाद की परिभाषा ऐसी है कि इसके दायरे में कोई भी ट्रेडयूनियन कार्रवाई, कोई भी जनान्दोलन सिमट जायेगा। पुलिस के हाथों में बेपनाह अधिकार दे दिये गये हैं।

एक बार पकड़े जाने पर छह महीने तक जमानत मिल ही नहीं सकती। सुनवाई बन्द कमरे में होगी और गवाहों की पहचान गुप्त रखी जायेगी। इसके अलावा इस कानून के तहत सरकार जब चाहे किसी संगठन को प्रतिबंधित कर सकती है।

जाहिर है कि संविधान में मिले जनतांत्रिक अधिकार इस कानून के लागू होते ही बेमतलब के हो जायेंगे, पुलिस फटाफट इन्साफ करेगी और कहीं कोई अपील नहीं, किसी अदालत में कोई सुनवाई नहीं।

लेकिन एक अदालत है जहां आने वाले दिनों में पोटो जैसे कानूनों को बनाने वालों की सुनवाई होगी – वह है जनता की अदालत। हमें उसी दिन की तैयारी करनी है जब जनता की अदालत बैठेगी और तमाम जालिम लुटेरों, उनके राजकाज, उनके कानून-संविधान के खिलाफ फैसले सुनाये जायेंगे।

"तीन करने योग्य व तीन न करने योग्य" तीन बुनियादी सिद्धांत हैं जिनका कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को अवश्य पालन करना चाहिए।

महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान हमने ल्यू शाओ-ची और लिन प्याओ की अगुवाई वाले दो बुर्जुआ हेडक्वार्टरों को नेस्तनाबूद किया और शानदार जीतें हासिल कीं। लेकिन इसके बावजूद संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। समाज में वर्ग-संघर्ष और पार्टी में दो लाइनों का संघर्ष लम्बे समय तक जारी रहेगा। सभी कम्युनिस्टों को "तीन करने योग्य व तीन न करने योग्य" के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सभी गलत कार्यदिशाओं और रुझानों के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस करना चाहिए, जिससे वह अगली कतारों के कार्यकर्ता बन सकें जो सर्वहारा की तानाशाही के अन्तर्गत क्रांति को जारी रखते हैं।

संशोधनवाद की बजाय मार्क्सवाद लागू करने के लिए एक कम्युनिस्ट को सबसे पहले **"गम्भीरतापूर्वक मार्क्सवाद की पढ़ाई व अध्ययन करना चाहिए और उस पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए"**, ताकि वह जटिल संघर्ष के दौरान सही दिशा और सही रास्ते को समझ सके, और दृढ़निश्चय के साथ अध्यक्ष माओ को सर्वहारा क्रांतिकारी दिशा को लागू कर सके। हम कम्युनिस्टों को ईमानदारी के साथ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा को भली-भाँति अध्ययन करना और समझना चाहिए, तीन महान क्रान्तिकारी आंदोलनों की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, अध्यक्ष माओ की क्रान्तिकारी कार्यदिशा की स्पिरिट और मूलतत्व की अपनी समझदारी को और गहरा बनाना चाहिए और लगातार इसे लागू करने के बारे में अपनी सोच के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। केवल इसी तरह हम असली और नकली मार्क्सवाद में सही और गलत कार्यदिशा में, और गलत और सही विचारों में भेद करने की अपनी काबिलियत को लगातार बढ़ा सकते हैं। केवल इसी रास्ते हम धोखा खाने से बच सकते हैं, बुर्जुआ और संशोधनवादी विचारों के नुकसानदायक प्रभावों को बेअसर कर सकते हैं, सर्वहारा स्थिति को अपना सकते हैं, समाजवादी राह पर लगातार डटे रह सकते हैं और संशोधनवाद की बजाय मार्क्सवाद को लागू करते रह सकते हैं।

संशोधनवाद नहीं बल्कि मार्क्सवाद लागू करने के लिए एक कम्युनिस्ट को संशोधनवादी और बुर्जुआ विश्व दृष्टिकोण की आलोचना जरूर करनी चाहिए। यह महान क्रांतिकारी आलोचना करने का मतलब है, बुर्जुआ विचारों को हराने के लिए सर्वहारा विचारों का इस्तेमाल करना, संशोधनवाद की आलोचना करने के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ त्से-तुङ विचारधारा का इस्तेमाल करना। अगर समाजवाद के दौर में, हम विस्तृत पैमाने पर यह आलोचना नहीं करते, तो संशोधनवादी और बुर्जुआ विचार खुल्लमखुल्ला फैलने, लोगों के दिमागों में जहर भरने और समाजवाद के आर्थिक आधार को तबाह करने में एक बेहद घातक भूमिका अदा करने, पार्टी को भ्रष्ट करने और सर्वहारा की तानाशाही को उखाड़ फेंकने की ओर ले जाने के लिए आजाद हो जायेंगे। सही समाजवादी दिशा पर जमे रहने और सर्वहारा की तानाशाही को मजबूत करने के लिए, हमें संशोधनवाद और बुर्जुआ विश्व दृष्टिकोण की जरूर आलोचना करनी चाहिए, और संस्कृति के तमाम क्षेत्रों समेत, अधिरचना में संघर्ष-आलोचना-रूपान्तरण को सही ढंग से अंजाम देना चाहिए। ईमानदार क्रान्तिकारी आलोचना करने के लिए, हमें एक दीर्घकालिक संघर्ष छेड़ने के विचार को अवश्य समझना चाहिए, पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा को विस्तार से समझना चाहिए और ल्यू शाओ-ची और लिन प्याओ द्वारा पेश किए गए नकारात्मक उदाहरणों का पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम गहराई से संशोधनवाद की आलोचना कर सकें। संघर्ष की सामान्य दिशा से भटकने के खतरे से बचने का सिर्फ यही रास्ता है और इसी रास्ते हम इस बारे में विभेद की एक स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं कि कार्यदिशा के दायरे में क्या आता है और क्या इससे अलग है। संशोधनवाद अभी भी आज की दुनिया में मुख्य खतरा है। मार्क्सवाद का अध्ययन करना और संशोधनवाद की आलोचना करना दो दीर्घकालिक कार्यभार हैं जो हमें पार्टी के सैद्धांतिक स्तर को ऊपर उठाने के काबिल बनाएंगे।

पार्टी के भीतर और बाहर, कम्युनिस्टों को सबसे बड़ी संख्या में एकजुट होना चाहिए और जनता से बेलागलपेट होना चाहिए। जब हम कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सभी प्रकार के सवालों के हल निकालते हैं, तो हमें कम्युनिस्ट भावना प्रदर्शित करनी चाहिए, पूरी पार्टी और इसकी एकता को बुनियादी चीज समझना चाहिए और पार्टी के हितों को प्रस्थान-बिन्दु मानना चाहिए – ये पार्टी की एकता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्रान्तिकारी कतारों में कम्युनिस्टों को एकता के आदर्शों के रूप में काम करना चाहिए। काडर अपने रहने वाले इलाके में ही पार्टी के भीतर काम कर रहे हों या बाहर, चाहे वे सैनिक काडर हों या स्थानीय (नागरिक), चाहे पुराने हों या नए, उन्हें पार्टी और जनता के हितों को ही अपने प्रस्थान-बिन्दु के रूप में लेना चाहिए। उनके पास एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के महत्व को समझना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जिससे वे पार्टी की एकता को मजबूत कर सकें। गलतियां करने वाले साथियों के साथ व्यवहार में, काडरों को दो तरह के अन्तरविरोधों के बीच कड़ाई से भेद करना चाहिए। उन्हें अपने साथियों की गलतियों को पहचानने और सुधारने में गर्मजोशी के साथ सहायता करनी चाहिए और सामूहिक कार्यों में भागीदारी करने के लिए, कार्यदिशा और उससे अलग चीजों के बीच में स्पष्ट विभेद के द्वारा, उन्हें जीतना चाहिए। मार्क्सवादी और लेनिनवादी सिद्धांतों के आधार पर इस तरह हम अपने विचारों और कार्रवाइयों में एकता स्थापित कर सकेंगे, एकता मजबूत कर सकेंगे और साथ संघर्ष कर सकेंगे। संक्षेप में, कम्युनिस्ट पार्टी के हम सभी सदस्यों को जनता से खुला होना चाहिए, हमें किसी भी हालत में अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, कट्टरता नहीं दिखलानी चाहिए या गुप्त रूप से गुटवादी गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए। हमें प्रसिद्धि या लाभ से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। हमें कभी अपने व्यक्तिगत हितों से प्रस्थान नहीं करना चाहिए, न ही धोखेबाजी के हथकण्डों से कोई पद प्राप्त करना चाहिए। हमें हर मामले में अध्यक्ष माओ और केन्द्रीय कमेटी के निर्देशों का पालन करना चाहिए और पार्टी की एकता तबाह करने के लिए की जा रही सभी गतिविधियों के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक संघर्ष करना चाहिए।

कम्युनिस्टों को हमेशा ईमानदार, खरा और खुला होना चाहिए। ऐसा होने के लिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को दृढ़ रुख अपनाना चाहिए और अपना झण्डा बुलन्द रखना चाहिए ताकि सभी उसे देख सकें। हमें सिद्धांत पर डटे रहने और संघर्ष करने का साहस करना चाहिए। हमें हर महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल पर अपनी मान्यताएं स्पष्ट तौर पर सूत्रीबद्ध करनी चाहिए, एक साफ रुख अख्तियार करना चाहिए, चाहें वह स्वीकृति का हो या विरोध का, और हमें अस्पष्ट और अनेकार्थी रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए। खुले और निष्कपट होने के लिए, हमारा रुख तथ्यों से सत्य को निकालने का भी होना चाहिए। जब हम बोलते हैं या किसी सवाल को हल करते हैं तो हमें बिल्कुल वैज्ञानिक रवैया अपनाना चाहिए, न हमें चीजों के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताना चाहिए और न ही घटाकर। सरलता से बोलना चाहिए, सच पर कायम रहना चाहिए और कामों को ईमानदारी से अंजाम देना चाहिए। हमें कथनी और करनी में भेद वाली, ऊपरी तौर पर मानने पर दिल से न मानने वाली, सही और गलत को गड्डमड्ड कर देने वाली कपटी कार्यशैली का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए। हम कथनी और करनी में भेद रखकर नहीं काम कर सकते। यह नहीं होना चाहिए कि बैठक में जिस बात का समर्थन किया था, बैठक के बाद उसका खण्डन कर दें। हम घमण्ड से भरकर फूलना, अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश करना और कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर घटिया बुर्जुआ कार्यशैली अपनाना तो और भी गवारा नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट सर्वहारा के हिरावल हैं और हमें राजनीतिक मोर्चे पर खुला और निष्कपट होना ही चाहिए, हमें खुले दिल का, विनम्र और दूरदर्शी होना चाहिए। हमें न घमण्डी होना चाहिए और न ही चिड़चिड़ा और सख्ती से अपनी "चीर-फाड़" करनी चाहिए। अगर हम गलती करते हैं, तो हमें ईमानदारी से उनसे सीखना चाहिए और वास्तव में उन्हें ठीक करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं काम करना चाहिए जैसे कि हम ठीक होने से बचने के लिए अपनी बीमारी छुपाना चाहते हों। हमें अपनी गलतियां नहीं छुपानी चाहिए न ही आलोचना स्वीकार करने से इंकार करना चाहिए, न ही ऐसा होना चाहिए कि हम प्रशंसा का तो आनन्द उठाएं पर हमें आलोचना सुनना गवारा न हो। हमें अपनी गलतियों की लीपापोती तो और भी कम करनी चाहिए और न ही उन्हें दूसरों के सिर मढ़ना चाहिए। अध्यक्ष माओ ने कहा है: **"मैं मानता हूं कि हमें चीजों को ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी के बिना इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना बिल्कुल असंभव है।"** (**माओ त्से-तुङ, संकलित रचनाएं, खण्ड-3, "पार्टी की कार्यशैली में सुधार करो", अंग्रेजी संस्करण, पृ. -44**)। हमें अध्यक्ष माओ की इस शिक्षा का अवश्य अनुसरण करना चाहिए और स्पष्ट वक्ता, खरा और ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए।

"तीन करने योग्य व तीन न करने योग्य" के सिद्धांत वे शक्तिशाली सैद्धान्तिक हथियार हैं जो दो लाइनों का संघर्ष चलाने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें अध्यक्ष माओ की इन तीन सिद्धांतों से सम्बन्धित शिक्षाओं का अवश्व पालन करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए और दीर्घकालिक संघर्ष के दौरान इन्हें अपने दिल में एकदम उतार लेना चाहिए, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। हमें इन सिद्धांतों पर जमे रहना चाहिए, पार्टी के भीतर दो लाइनों के संघर्ष को सक्रिय और सही तरीके से चलाना चाहिए, ताकि समाजवादी क्रान्ति को अंत तक चलाया जा सके।

(अगले अंक में नया अध्याय: पार्टी का केन्द्रीकृत नेतृत्व)

विशेष सामग्री

(चौदहवीं किश्त)

पार्टी की बुनियादी समझदारी

अध्याय - 5

पार्टी का "तीन करने योग्य व तीन न करने योग्य" का सिद्धांत

एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना मजदूर वर्ग क्रांति को कतई अंजाम नहीं दे सकता। लेनिन ने इस बात को बार-बार जोर देकर कहा था। स्तालिन और माओ ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया और बीसवीं सदी की सभी सफल सर्वहारा क्रान्तियों ने भी इसे सत्यापित किया।

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों का निर्धारण किया और इसी फौलादी सांचे में बोल्शेविक पार्टी को ढाला। चीन की पार्टी भी बोल्शेविक पार्टी की ही उत्तराधिकारी थी। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान, समाजवादी समाज में वर्ग-संघर्ष का संचालन करते हुए माओ के नेतृत्व में चीन की पार्टी ने अन्य युगान्तरकारी सैद्धान्तिक उपलब्धियों के साथ-साथ लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तों को भी और आगे विकसित किया।

सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए बुर्जुआ तत्वों ने सबसे पहले यही जरूरी समझा कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी का चरित्र बदल दिया जाये। हमारे देश में भी संसदीय रास्ते की अनुगामी नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं। भारतीय मजदूर क्रांति को सफल बनाने के लिए भारत में भी सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सर्वोपरि है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि मजदूर वर्ग यह जाने कि असली और नकली कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है और एक क्रान्तिकारी पार्टी कैसे खड़ी की जानी चाहिए।

इसी उद्देश्य से, फरवरी, 2001 अंक से हमने एक बेहद जरूरी किताब 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' के अध्यायों का किश्तों में प्रकाशन शुरू किया है। इस अंक में चौदहवीं किश्त दी जा रही है। यह किताब सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान पार्टी-कतारों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तैयार की गयी श्रृंखला की एक कड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस (1973) में पार्टी के गतिशील क्रान्तिकारी चरित्र को बनाये रखने के प्रश्न पर अहम सैद्धान्तिक चर्चा हुई थी, पार्टी का नया संविधान पारित किया गया था और संविधान पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। इसी नई रोशनी में यह पुस्तक एक सम्पादकमण्डल द्वारा तैयार की गयी थी। मार्च, 1974 में पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, शंघाई से इस पस्तक के प्रथम संस्करण की 4,74,000 प्रतियां छपीं। यह पुस्तक पहले चीनी भाषा से फांसीसी भाषा में अनूदित हुई और 1976 में प्रकाशित हुई। फिर नामेन बेथ्यून इस्टाच्यूट, टोरण्टो (कनाडा) ने इसका फांसीसी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया और 1976 में ही इसे प्रकाशित भी कर दिया। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पुस्तक के इसी अंग्रेजी संस्करण से किया गया है।

- सम्पादक

चीन में खुले बाजार की नीतियों का "चमत्कार"

छंटनी-तालाबन्दी-महंगाई-बेकारी-तबाही और भ्रष्टाचार

मेहनतकशों की हड़तालों-प्रदर्शनों का अन्तहीन सिलसिला

योगेश पन्त

ज्यादा दिन नहीं बीता जब समूची दुनिया का पूंजीवादी मीडिया चीन में खुले बाजार की नीतियों के "चमत्कारों" पर गदगद भाव से चर्चा किया करता था। लेकिन जब सच्चाई का जादू सिर चढ़कर बोलने लगता है तो नकली "चमत्कारो" की हवा निकल जाती है। अब वही पूंजीवादी मीडिया बुझे मन से चीन के आर्थिक "चमत्कारों" की जगह वहां फैले मजदूरों के असन्तोष, हड़तालों, प्रदर्शनों, हिंसक वारदातों की चर्चा कर रहा है।

आर्थिक विकास के पूंजीवादी आंकड़े उस तबाही के सागर को नहीं ढंक सकते जिसकी बुनियाद पर अमीरी और ऐय्याशियों के टापू उठ खड़े होते हैं। चीन के कम्युनिस्ट नामधारी शासक जैसे-जैसे खुले पूंजीवाद की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे पूंजीवाद की सारी बुराइयां नंगे रूप में उजागर होती जा रही हैं। छंटनी-तालाबंदी-बेकारी-महंगाई-भ्रष्टाचार ही नहीं आज वेश्यावृत्ति, शराबखोरी व जुआखोरी आदि तमाम पूंजीवादी सामाजिक बीमारियां चीन को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। नतीजतन पूरा चीनी समाज भीषण सामाजिक तनाव का शिकार है। चीनी मेहनतकश जनता खुले बाजार की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा केवल हड़तालों-प्रदर्शनों के जरिये ही नहीं व्यक्त कर रहा है, गुस्से के साथ-साथ नफरत और हताशा भी इतनी गहरी है कि छंटनीशुदा मजदूर कारखाना मैनेजरों की हत्याएं तक कर रहे हैं।

सच तो यह है कि 1976 में माओ त्से-तुङ की मृत्यु के बाद खूनी तख्तापलट करके जबसे कम्युनिस्ट का चोला ओढ़े पूंजीवादी हत्यारों ने सत्ता संम्हाली है और समाजवाद को पीछे धकेलते हुए पूंजीवादके रास्ते पर कदम बढ़ाया है तबसे वे एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाये हैं। तबसे एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब हड़तालों-प्रदर्शनों से उनका सामना न होता हो। दमन के मामले में चीन के ये नये कम्युनिस्ट नामधारी पूंजीवादी हुक्मरान सैनिक तानाशाहों को भी पीछे छोड़ चुके हैं लेकिन चीनी मेहनतकश जनता के विरोध प्रदर्शन कम होने की बजाय लगातार बढ़ते ही गये हैं। एक अनुमान के अनुसार चीन में आजकल हर रोज लगभग तीन सौ विरोध प्रदर्शन होते हैं जिनमें हजारों-लाखों लोग शामिल होते हैं।

पिछले मार्च महीने में चीन के हीलोगिजाङ प्रान्त, हेबेई, लियाओनिङ, जिलिन और शान्दोग प्रान्तों में प्रदर्शनों-हड़तालों का तांता लगा रहा जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत किया।

इण्टरनेट से प्राप्त जेम्स कोनाची की एक रिपोर्ट (23 मार्च 2002) के अनुसार समूचे मार्च महीने में चीन के सभी प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में छंटनीशुदा मजदूरों के जबर्दस्त प्रदर्शन हुए हीलोगिजाङ प्रान्त के दाकिङ जिले में, जो तेल उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है, 1 मार्च से शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे-धीरे कई अन्य प्रान्तों में फैल गया। दाकिङ में चीन में ऊर्जा क्षेत्र की ध्वजपोत मानी जाने वाली कम्पनी पेट्रोचाइना की प्रमुख सहायक कम्पनी दाकिङ पेट्रोलियम स्थित है। इस कम्पनी से पिछले तीन सालों में 86,000 से अधिक मजदूरों की छंटनी हो चुकी है। छंटनी की वजह यह थी कि पेट्रोचाइना कम्पनी को हांगकांग और न्यूयार्क के स्टाक एक्सचेंज में शामिल किया गया था और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में होड़ में टिकने के लिए उसे अपनी लागत हर हाल में घटानी थी। इन छंटनीशुदा मजदूरों के लिए कम्पनी ने धोखाधड़ी से छंटनी के एवज में एक ऐसी स्कीम के लिए राजी किया जिसका नतीजा यह हुआ कि मजदूरों के पास वास्तव में एक धेला भी नहीं बचता। मजदूरों ने कम्पनी की इस धोखाधड़ी के खिलाफ सरकारी अधिकारियों से लेकर सरकारी ट्रेडयूनियनों तक गुहार लगायी लेकिन किसी ने कान नहीं दिया। तब आखिरकार उन्होंने दाकिङ के छंटनीशुदा मजदूरों की एक कामकाजू यूनियन कमेटी बनाकर संघर्ष की शुरुआत कर दी।

इस नयी यूनियन कमेटी के आह्वान पर पहली मार्च को पहले प्रदर्शन में 3000 मजदूर आये लेकिन 4 मार्च को प्रदर्शन के दूसरे दिन 50,000 मजदूर जमा हो गये। उसके बाद हर रोज कम्पनी के हेडक्वार्टर पर 5000 से लेकर 30,000 तक मजदूर प्रदर्शन में शामिल होते रहे। धीरे-धीरे यह प्रदर्शन पश्चिमी प्रान्त जिनजियाङ के तेल क्षेत्रों के साथ हेबेई, लियाओनिङ, जिलिन और शान्दोङ प्रान्तों में भी फैल गया।

सरकार के अधिकारियों ने दमन के हथकण्डे अपनाकर मजदूरों के असन्तोष को दबाने की कोशिश की लेकिन लियाओनिङ प्रान्त में तो मजदूरों के एक जबर्दस्त जनउभार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। लियाओनिङ प्रान्त समाजवाद क दौर के राजकीय उद्यमों का निजीकरण करने की नीतियों का सबसे बुरी तरह शिकार हुआ है। पिछले पांच वर्षों में इन राजकीय उद्यमों से चार करोड़ से अधिक मजदूरों को निकाला जा चुका है।

लियाओनिङ प्रान्त के दो प्रमुख शहरों लियाओयाङ और शेनयाङ में भीषण बेरोजगारी की स्थिति है और तरह-तरह की सामाजिक समस्याएं फैल चुकी हैं। एक अनुमान के अनुसार लियाओयाङ शहर की कुल मजदूर आबादी का आधे से अधिक **जियागाङ** हैं – अर्थात उनके मालिक उन्हें सिर्फ 180 युवान (लगभग 1000 रुपये) मासिक भत्ता देते हैं। यह भी मजदूरों को नहीं मिल पाता क्योंकि कम्पनियां खुद को दिवालिया घोषित कर देती हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा राजकीय उद्यमों की परिसम्पत्तियों की लूटखसोट इन कम्पनियों को दिवालिया बना देती है।

न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लियाओनिङ प्रान्त के कुशान क्षेत्र के 10 हजार से अधिक छंटनीशुदा कोयला मजदूरों ने छंटनी के एवज में मिलने वाले पैसे का भुगतान न होने पर मार्च महीने के मध्य में सड़कों और रेल लाइनों को जाम कर दिया था।

एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 11 और 12 मार्च को लियाओनिङ प्रान्त की राजधानी लियाओयाङ में छह प्रमुख कारखानों से छंटनी किये गये 7000 मजदूरों ने नगर के टाउनहाल पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाये, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित दूसरी सुविधाएं बहाल की जाएं। उनकी मांग यह भी थी कि उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये जो पेंशन की रकम हड़प ले रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल अधिकांश मजदूर लियाओयाङ फेरो-एलाय कम्पनी में काम करते थे और पिछले साल अक्टूबर-नवम्बर में कारखाने में तालाबन्दी के बाद हुए जुझारू विरोध प्रदर्शनों में भी शामिल हुए थे।

दो दिनों तक अधिकारियों ने इन ताजा प्रदर्शनों पर कोई अड़ंगेबाजी नहीं की लेकिन पुलिस ने 17 मार्च को एक 53 वर्षीय मजदूर नेता याओ फूक्सिन को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन 30 हजार से अधिक मजदूरों ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन किया। लेकिन, सरकार का दमनचक्र जारी रहा। तीन और नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कई दिनों तक उग्र प्रदर्शन होते रहे।

बेबस हताश मजदूर मैनेजरों की हत्याएं कर अपना गुस्सा उतार रहे हैं।

1949 की चीनी क्रान्ति के बाद 1976 तक, जब तक वहां का मेहनतकश अवाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में समाजवाद की ओर लम्बे डग भर रहा था, हर चीनी नागरिक को न केवल रोजगार की गारण्टी थी बल्कि उसकी जिन्दगी को हर तरह की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन आज चीन की फिजां पूरी तरह बदल चुकी है। आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य मजदूरों की नहीं देशी-विदेशी पूंजीपतियों की लूट का चौकीदार बन चुका है। चीनी मजदूर-मेहनतकश आज कम्युनिस्ट नामधारी पूंजीवादी शासकों की खुले बाजार वाली नीतियों तले उसी तरह पिस रहा है जैसे भारत या किसी भी पूंजीवादी देश का मजदूर मेहनतकश। वहां भी तमाम ट्रेड यूनियनें जो कल तक मेहतनकशों की रहनुमाई करती थीं, आज सरकारी दलाल बन चुकी हैं। ऐसे में आज मजदूर वहां बेबस है। इस बेबसी को प्रदर्शनों में शामिल जियाओ नामक एक मजदूर ने न्यूयार्क टाइम्स के पत्रकार से इन शब्दों में बयान किया, **"हम इस तरह जीते नहीं रह सकते। हमारी कोई नहीं सुनता। हम सरकारी ट्रेड यूनियनों के पास अपनी समस्याएं लेकर नहीं जा सकते। वे कम्युनिस्ट पार्टी की (सरकार की) यूनियनें हैं, हमारी नहीं।"** वाशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार से झाङ नामक एक मजदूर ने खुले बाजार की नीतियों की असलियत इन शब्दों में बतायी, **"इनसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर आदमी चीन के चमत्कारों की बात कर रहा है। असलियत यह है कि यहां कोई चमत्कार नहीं हो रहा है।"**

चीन के एक आम मजदूर की बेबसी को समझने के लिए ये बयान काफी हैं। इसी बेबसी और हताशा में

(पेज 10 पर जारी)

मुनाफाखोरों के हक में श्रम कानून बदलने के खिलाफ

राजधानी रोम की सड़कों पर मेहनतकशों का सैलाब

(कार्यालय प्रतिनिधि)

इटली की ऐतिहासिक राजधानी रोम का ऐतिहासिक चौक – सर्कस मैक्सिमस। पुराने जमाने में इस चौक पर गुलामों के मालिकों और रोमन गणतंत्र के नागरिकों (उस समय गुलामों को नागरिक नहीं माना जाता था) का जमावड़ा हुआ था। वे यहां बग्घियों की दौड़ देखकर मौजमस्ती करते थे। लेकिन पिछले 23 मार्च को इस चौक पर बिल्कुल अलग ही नजारा था। उस दिन भी यहां एक ऐतिहासिक जमावड़ा हुआ। लेकिन कोई खेल देखने या मौजमस्ती के लिए नहीं। उस दिन हवा में परचम और मुट्ठियां लहराते लाखों मेहनतकशों का सैलाब उमड़ पड़ा था – अपने हुक्मरानों को चेतावनी देने के लिए। यह था समूचे इटली से आये दस लाख से अधिक मेहनतकशों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, जिसमें बुलन्द आवाज में प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी सरकार को यह चेतावनी दी गयी कि मुनाफाखोरों के हक में मेहनतकशों के हकों पर डाकेजनी बन्द करो।

जिस तरह हमारे देश की सरकार देश-विदेश के मुनाफाखोरों की हवस शान्त करने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव कर मज़दूरों-मेहनतकशों का

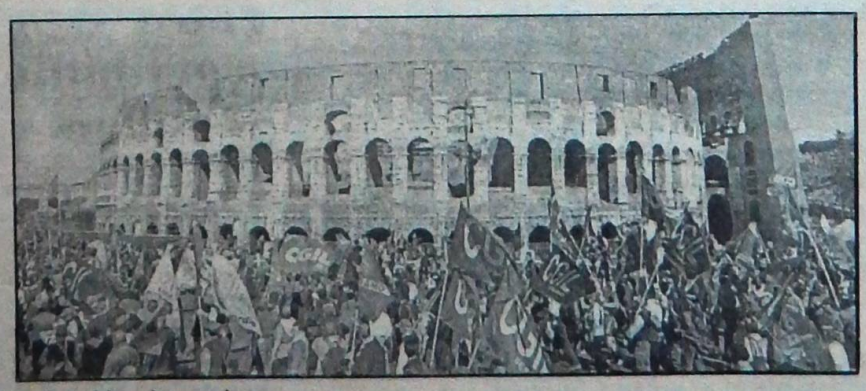

खून-पसीना बेरोक-टोक चूसने का इन्तजाम कर रही है उसी तरह का कानून इटली की सरकार भी थोपना चाहती है। खासकर सरकार इटली के श्रम कानूनों की एक अहम धारा-18 को बदलकर पूंजीपतियों को छंटनी-तालाबन्दी की खुली छूट देना चाहती है। यह हमारे देश के श्रम कानूनों की धारा 5-बी जैसी है जिसे वाजपेयी सरकार बदल रही है। मुनाफाखोरों के हक में श्रम कानूनों में इसी बदलाव के खिलाफ इटली की सबसे बड़ी और ताकतवर यूनियन सी.जी.आई.एल. के बुलावे पर राजधानी रोम की सड़कों पर यह जनसैलाब उमड़ पड़ा था।

इटली का मजदूर आन्दोलन यूरोप में सबसे ताकतवर मजदूर आन्दोलन में गिना जाता है। वहां मेहनतकशों ने शानदार लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं। यही वजह है कि वहां न केवल मजदूरों-कर्मचारियों को न केवल अच्छे वेतन-भत्ते मिलते हैं बल्कि सेवा शर्तें भी बेहद अच्छी हैं और रोजगार काफी सुरक्षित है। मजदूरों को मालिक आसानी से काम से नहीं हटा सकते। लेकिन जबसे पूरी दुनिया के पूंजीपतियों का संकट बढ़ा है तबसे अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए दुनिया भर के पूंजीपतियों ने मजदूरों के हकों पर खुला डाका डालने की कोशिश तेज कर दी है। दुनिया के पूंजीपतियों की इसी डकैती का ही नाम है भूमण्डलीकरण। इसी के तहत जनता के खून-पसीने पर खड़े किये सरकारी कल-कारखानों को मिट्टी के मोल पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है, विदेशी पूंजी को बुलावा दिया जा रहा है और इसी के तहत श्रम कानूनों को भी बदला जा रहा है और काफी कुर्बानियां देकर हासिल किये गये मजदूरों के अधिकारों को हड़पा जा रहा है।

लेकिन इटली के मेहनतकशों ने अपने संघर्षों के शानदार इतिहास को दुहराते हुए अपने शासकों को यह चेता दिया है कि उनके मंसूबे आसानी से कामयाब नहीं हो पायेंगे। इटली के मजदूर-मेहनतकश आखिरी दम तक अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए लड़ने पर आमादा दिखायी दे रहे हैं। सरकार ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो अप्रैल महीने में और जोरदार संघर्ष की तैयारी चल रही है। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार श्रम कानूनों को बदलने पर अड़ी रही तो अप्रैल में पूरे देश में आम हड़ताल शुरू हो जायेगी। सी.जी.आई.एल. के नेतृत्व में यूनियनें इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं।

ऐसा लगता है कि इस चेतावनी के बावजूद इटली की सरकार अपना इरादा बदलने के लिए तैयार नहीं है।

(पेज 10 पर जारी)

कविता

– बेर्टोल्ट ब्रेष्ट

कौन तोड़ेगा तेरी बेड़ियां
बतला ऐ गुलाम ?
वो जो ग़रकाब है तारीक बयाबानों में
उनके ही कानों में पहुंचेगी तेरी आहो-फुगां
हम-नफस तुझको छुड़ा सकते हैं
जो खुद हों गुलाम...
या तो सब साथ या कोई नहीं
कोई भी नहीं
या तो हर चीज या फिर
कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं
क्या ये तनहाई बदल सकती है
तेरी तस्वीर ?
या तो बन्दूक तेरे वास्ते
या फिर जंजीर !

दिल्ली में नगर निगम चुनाव

मगरूर, सत्ता-मद में चूर भाजपाइयो, देखो जनता ने तुम्हें फिर खारिज कर दिया है क्या अब अपने लिए नयी जनता चुनोगे?

(बिगुल संवाददाता)

दिल्ली। पिछले दिनों हुए चार विधानसभा चुनावों की कहानी दुहराते हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी जनता ने भाजपाइयों को खारिज कर दिया है। भाजपाइयों की इतनी बुरी तरह मिट्टी पलीद होगी इसका अनुमान तमाम माहिर चुनाव विश्लेषकों को भी नही था। कुल 134 सीटों में से भाजपा को बमुश्किल तमाम 16 सीटें मिली हैं। कांग्रेसियों ने 107 सीटें झटक ली हैं। बाकी निर्दलियों और दूसरी पार्टियों के हत्थे आयी हैं।

इस करारी हार से अपनी झेंप मिटाने के लिए हालांकि भाजपाई पार्टी की अन्दरूनी खींचतान और प्रचार-प्रसार में कमी को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने कोई कोर-कसर बाकी न रखी थी। उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, शराब भी पानी की तरह बहायी, फिल्मी सितारों के चेहरे दिखाकर लोगों को रिझाया, ईमानदारी और अच्छे चरित्र का हमेशा की तरह जोर-जोर से डागा-बाजा बजाया, मगर कुछ काम न आया। शिलादान काम न आया, आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भी काम न आया – हर हिकमत, हर हथकण्डा अपनाया, पर कुछ भी काम न आया।

हालांकि पूंजीवादी जनतंत्र के चुनावी खेल के नतीजों से कोई दूरगामी राजनीतिक नतीजे नहीं निकाले जा सकते क्योंकि जनता बेखौफ होकर किन्हीं मुद्दों पर वोट डालने की हालत में नहीं रहती। उसे नागनाथ या सांपनाथ में से ही किसी को चुनना होता है। वोट भी जाति-धरम, क्षेत्र, पैसे के जोर पर, बन्दूकों के जोर पर, तमाम पिछड़ी भावनाएं भड़काकर डलवाये जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ फौरी नतीजे तो निकाले ही जा सकते हैं। जैसे इस चुनाव में यह नतीजा तो निकाला ही जा सकता है कि भाजपाइयों के चाल-चेहरा-चरित्र के बारे में जनता का एक हिस्सा अच्छी तरह समझ चुका है।

इस चुनाव के नतीजों से यह नतीजा निकालना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की आम जनता ने हवाई राष्ट्र प्रेम, 'राष्ट्रीय भावनाओं के प्रकटीकरण' से ज्यादा रसोई गैस और केरोसिन की बढ़ी कीमतों, बढ़ती बेकारी, प्रदूषण के नाम पर मजदूरों के उजाड़ने, झुग्गी-झोपड़ियों का सफाया करने आदि के मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दिया है। ऐसा इसलिए कि इस चुनाव में कुल 42 फीसदी लोगों ने ही वोट डाले थे और अखबारों के मुताबिक अमीरों के मुहल्लों-कालोनियों से लोग वोट डालने नहीं के बराबर निकले। मतलब कि अधिकांश वोटर गरीब और आम मध्यम वर्ग के थे। यही वर्ग दिल्ली का आम आदमी कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह कि दिल्ली के आम आदमियों की जमात ने भाजपाइयों को दुत्कार-फटकार दिया है।

लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि दिल्ली की आम जनता ने कांग्रेसियों में भरोसा जाहिर किया है। यह चुनाव भी तमाम आम चुनावों की तरह विकल्पहीनता का चुनाव था। वही नागनाथ या सांपनाथ के बीच का चुनाव। भाजपाइयों के चाल-चेहरा-चरित्र और भाजपा सरकार की नीतियों से लोगों का गुस्सा कांग्रेस की झोली में वोट बनकर गिरा है। अलबत्ता, कांग्रेसियों को यह भरम जरूर हो रहा होगा कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं।

जिस दिन दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हुए उस दिन आकाशवाणी दिल्ली से रात ग्यारह बजे प्रसारित हुए एक समाचार बुलेटिन में चुनाव नतीजों के ठीक बाद एक दूसरी खबर यह प्रसारित हुई – "प्रधानमंत्री बाजपेयी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तनाव की हालत को देखते हुए युद्ध की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।" हो सकता है चुनाव नतीजों के तुरन्त बाद प्रसारित यह खबर महज एक संयोग हो। लेकिन चार विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली नगर निगम के अहम चुनाव में पटखनी खाने के बाद क्या इस संभावना से पूरी तरह इन्कार किया जा सकता है कि भाजपाई संघ परिवार के मार्गदर्शन में रामराग और श्मशानी नाच के साथ-साथ युद्ध का राग भी अलापना शुरू कर दें, यूं भी केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार का कार्यकाल धीरे-धीरे खत्म होने की ओर ही बढ़ रहा है और देखते-देखते अगले आम चुनाव भी सिर पर आ धमकेंगे।

वैसे संघ परिवार रामराग और युद्धराग अलापने के साथ-साथ एक और काम कर सकता है। जर्मनी के क्रान्तिकारी कवि बेर्टोल्ट ब्रेष्ट की एक कविता की लाइनों को सार्थक बनाते हुए वह अपने लिए एक नयी जनता चुनने का काम कर सकता है। आखिर जनता तो उन्हें चुन नहीं रही है तो ऐसे में 100 फीसदी गारण्टी वाले इस नुस्खे के बारे में संघ परिवार क्यों नहीं सोचता?

(पेज 4 से आगे)

नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा...

असली चेहरा। यही देउबा जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो माओवादियों को जन प्रतिनिधि मानते थे, आज उन्हें वही आतंकवादी नजर आने लगे।

देउबा अपनी इस महत्वपूर्ण भारत यात्रा में अपनी पीठ ठुकवां कर, सहायता के ठोस आश्वासन लेकर भले ही बहुत खुश नजर आयें, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि विदेशी मदद और तानाशाही के दम पर जन ज्वार को कुचला नहीं जा सकता। देउबा जी को अपना इतिहास का ज्ञान दुरुस्त करने की जरूरत है।

(पेज 8 से आगे)

चीन में भारी उथल-पुथल...

डूबकर कुछ छंटनीशुदा मजदूरों ने सरकारी मालिकाने वाली फैक्टरियों के तीन मैनेजरों को मार डाला। मजदूरों द्वारा हताशा में इस तरह की हत्याएं उन क्षेत्रों में हो रही हैं जहां सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है और मजदूरों की जबरिया छंटनी की जा रही है। इस तरह की घटनाओं का सबसे अधिक शिकार मध्य चीन का हुबेई प्रान्त है जो माओवादी चीन में भारी उद्योगों का पालना कहा जाता था। लेकिन अब यह क्षेत्र उद्योगों की कब्रगाह में तबदील हो चुका है।

ये घटनाएं खुले बाजार के "चमत्कारों" की पोल तो खोल ही रही हैं लेकिन साथ ही ये आने वाले समय के उन तूफानों का संकेत भी दे रही है जो चीन के आसमान में मंडरा रहा है। एक गैरसरकारी अनुमान के अनुसार आज चीन में कुछ 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है यह खुद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जालिम नौकरशाह भी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल खुद पार्टी की एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गयी थी: **"अगर अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को एक मंजिल पर रोका न गया तो समाजवाद में व्यापक जनसमुदाय के सहज विश्वास को नष्ट होने से नहीं रोका जा सकता। इससे पार्टी में उनका भरोसा डगमगा जायेगा और यहां तक कि जारी सुधारों की गाड़ी पटरी से उतर जायेगी और सामाजिक उथल-पुथल मच जायेगी।"**

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की महान विरासत और समाजवाद की महान उपलब्धियों को कलंकित करने वाले पार्टी और राज्य में कब्जा जमाए हुए पूंजीपतियों के टट्टू हत्यारे नौकरशाहों को भला कौन बताये कि खुले बाजार और समाजवाद के घिनौने घालमेल वाले खूनी समाजवाद और उसकी झण्डाबरदार पार्टी चीनी जनता का विश्वास पहले ही टूट चुका है। चीन में आज जो हो रहा है वह एक भीषण सामाजिक उथल-पुथल नहीं तो और क्या है। सोचने की बात तो सिर्फ यह है कि चीनी मेहनतकश अवाम कब इन पूंजीवादी लुटेरों के खिलाफ फैसलाकुन जंग के लिए उठ खड़ी होती है। आज चीन में जो संकेत मिल रहे हैं क्या वे एक नये मुक्तियुद्ध की भूमिका लिख रहे हैं? इस सवाल का जवाब 'हां' हो, यह दुनिया के सभी मेहनतकशों का सपना होना चाहिए।

(पेज 8 से आगे)

रोम की सड़कों पर मेहनतकशों का सैलाब...

23 मार्च के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने टी.वी. पर कहा कि प्रदर्शन के बावजूद उनकी सरकार श्रम कानूनों को बदलने से पीछे नहीं हटने वाली। उसने हेकड़ी के साथ कहा कि देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यह जरूरी है। लेकिन इटली के मेहनतकशों पर पूंजीपतियों की पिट्ठू सरकार की चिकनी-चुपड़ी गोल-मोल बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि उनके देश के नेता जब देश के आर्थिक विकास की रट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पूंजीपतियों के मुनाफे का विकास।

देश के कोने-कोने से 10,000 विशेष बसों, 60 रेलगाड़ियों और यहां तक कि विशेष रूप से किराये पर लिये पानी के जहाजों में भरकर आये लाखों मजदूर सरकार को झुकाने के मजबूत इरादों के साथ आये थे। प्रदर्शन में शामिल एक मजदूर महिला ने एक पत्रकार से कहा कि "मैं यहां अपने लिए नहीं अपने 13 महीनें की बच्ची के भविष्य के लिए आयी हूं। मैं उन अधिकारों के लिए लड़ना चाहती हूं जो मेरी बच्ची को उस समय मिलने चाहिए जब वह काम करना शुरू करेगी।" एक दूसरे कारखाना मजदूर ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि "सरकार जल्दी ही महसूस कर लेगी कि उसकी जमीन खिसक रही है और वह उसी तरह सत्ता गवां बैठेगी जैसा 1994 में हुआ था।"

वह मजदूर 1994 में पेंशन सुविधाओं में कटौती के खिलाफ हुए जबर्दस्त प्रदर्शन की याद दिला रहा था। संयोग की बात है कि उस समय भी बर्लुस्कोनी ही प्रधानमंत्री थे। उन्हें उस समय इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। 23 मार्च को हुआ प्रदर्शन 1994 के प्रदर्शन से भी बड़ा था। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इटली के आधुनिक इतिहास का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। रोम के नगर अधिकारियों को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि प्रदर्शन में 7 लाख से अधिक लोग थे। हालांकि यूनियन नेताओं ने 30 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया है और कुछेक पत्रकारों ने भी बीस लाख का अनुमान लगाया है। इन दावों को अगर बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया मान लें तो इतना तय है कि प्रदर्शन में दस लाख से अधिक लोग शामिल हुए होंगे।

इटली के मजदूरों-मेहनतकशों के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद यह बात पूरे दावे और दमखम के साथ कही जा सकती है कि इटली के हुक्मरानों को ही नहीं दुनिया भर के पूंजीपतियों और उनकी पिट्ठू सरकारों को डरावने सपने आ रहे होंगे। वेटिकन सिटी में बैठे वृद्ध-जर्जर पोप का दिल भी जोर से धड़क रहा होगा। इक्कीसवीं सदी के इन शुरुआती वर्षों में यह कहना तो शायद बड़बोलापन होगा कि पूरे यूरोप को कम्युनिज्म का हौव्वा एक बार फिर सता रहा है लेकिन यह कहना सच्चाई का बयान होगा कि पूरे यूरोप में मजदूर आन्दोलन करवटें लेता दिखायी दे रहा है जिससे दुनिया में पूंजीवादी हुक्मरानों की बेचैनियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

राहुल फाउण्डेशन के नये प्रकाशन

बिगुल पुस्तिका-चार

अक्टूबर क्रान्ति की मशाल

दुनिया में मजदूरों-किसानों का पहला राज्य कायम करने वाली अक्टूबर क्रांति की हवाएं आने वाले दिनों फिर प्रचण्ड चक्रवाती तूफान बनकर उठेंगी। इक्कीसवीसदी भूकम्पकारी उथल-पुथल की सदी होगी। यह विश्वास एक विज्ञान सम्मत आस्था बनकर मेहनतकश अवाम की संकल्पशक्ति को नये सिरे से जगा सके, इसके लिए जरूरी है कि अक्टूबर क्रांति के इतिहास और उसके मार्गदर्शक सिद्धान्त का गहराई से अध्ययन किया जाय। साम्राज्यवाद के मौजूदा दौर में मजदूर क्रांन्तियों का स्वरूप और रास्ता क्या होगा यह तय किया जाये। बिगुल पुस्तिकाओं की शृंखला की यह कड़ी इसी दिशा मे एक कोशिश है।

पृष्ठ : ५२ मूल्य : रु १२.०० (बैकपेपर)

पेरिस कम्यून की अमर कहानी

बिगुल पुस्तिका-पांच

इतिहास में पहली बार मजदूरों की अपनी हुकूमत कायम करने वाले पेरिस कम्यूनको भले ही पूरे यूरोप के पूंजीपतियों ने मिलकर खून की नदियों में डुबो दिया, भले ही वह सिर्फ ७२ दिनों तक कायम रह सका लेकिन इस दौरान उसने दिखा दिया कि शोषण-उत्पीड़न, भेदभाव-गैरबराबरी से मुक्त समाज कायम करना कोरी कल्पना नहीं है। पेरिस कम्यून की पराजय ने दुनिया के मजदूर वर्ग को बेशकीमती सबक सिखाये। इन सबको आत्मसात करके ही सर्वहारा क्रांतियों की अगली कड़ियों का निर्माण सम्भव हो सका था और आगे भी होगा। पेरिस कम्यून का इतिहास क्या था, उसके सबक क्या हैं- यह जानना आम मेहनत आबादी के लिए बेहद जरुरी है। 'बिगुल' पुस्तिका की यह कड़ी इसी की जरुरत को पूरा करने की एक कोशिश है।

पृष्ठ : ४८ मूल्य रु.१२.०० (पेपर बैक)

उम्मीद एक जिंदा शब्द है

(दायित्व बोध के महत्पूर्ण सम्पादकीय लेखों का संकलन)

भारतीय समाज के आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक संकट, फासीवादी उभार की चुनौतियों, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की प्रकृति, स्वरूप और संकट, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के भटकावों, चुनौतियों, कार्यभारों और विकल्प के सवालों पर अठारह विचारोत्तेजक लेखों का एक जरुरी संग्रह ।

पृष्ठ : २२४ मूल्य : रु.६०.०० (पेपर बैक)

एनजीओ : एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र

आधिकारिक विद्वानों और जमीनी कार्यकर्ताओं की कलम से एन.जी.ओ. कुचक्र के सभी पहलुओं को उजागर करने वाली एक बेहद जरुरी किताब।

पृष्ठ : १२४ मूल्य : रु.२५.०० (पेपर बैक)

चुनावी राजनीति भण्डाफोड़ अभियान और जनसभा

'क्रान्तिकारी लोक-स्वराज्य ही जनता का सच्चा जनतंत्र होगा'

मर्यादपुर, मऊ। "54 वर्षों से चले आ रहे संसदीय जनतंत्र ने आज यह साबित कर दिया है कि यह मुट्ठी भर धनिकों के लिए जनतंत्र है और मेहनतकश आम जनता पर इन धनिकों की खुली तानाशाही है और चुनाव महज इस तानाशाही को बनाये रखने की संस्तुति मात्र है। चुना हुआ प्रतिनिधि आम जनता का नहीं बल्कि बमुश्किल 7% लोगों की नुमाइन्दगी करता है।" ये बातें 'चुनावी राजनीति के भण्डाफोड़' अभियान के तहत आयोजित विभिन्न सभाओं को सम्बोधित करते हुए 'नौजवान भारत सभा' के डा. जसवन्त ने कही।

डा. जसवन्त ने बोलते हुए आगे कहा कि, 'आम मेहनतकश जनता की आवाज को कुचलने के लिए देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल तैयार किया जा रहा है। पोटो जैसे कानून पास किये जा रहे हैं, जो जनता से उसके सभी जनतांत्रिक अधिकार छीन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार आम मेहनतकशों को जबरन सड़कों पर धकेलने वाली नीतियों को लागू कर रही है। धनिकों और बड़े कारखानेदारों के मनमाने छूट के लिए श्रमिक कानूनों में बदलाव कर रही है।' विगत दस वर्षों में ही यह नंगी आंखों से दिखाई पड़ रहा है कि नीतियों के मसले पर सभी पार्टियां एकजुट हैं, और उसने सिर्फ जनता को भरमाने के लिए जाति, धर्म और क्षेत्र के बनावटी मुखौटे लगाए हुए हैं। आज इस संसदीय राजनीति का कोई भी धड़ा जनपक्षधर नहीं रहा। जनता के सामने अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि वह इन अल्पसंख्यक धनिकों की सत्ता उखाड़ फेंके और बहुसंख्यक मेहनतकश अवाम का अपना 'लोक स्वराज्य' कायम करे।

सभा को सम्बोधित करते हुए देहाती मजदूर-किसान यूनियन के डा. दूधनाथ ने कहा कि , "आज इस चुनावी जनतंत्र की असलियत सामने आ चुकी है। इसका मज़दूर-किसान विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। एक तरफ यह खाद के दाम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ सेठों-साहूकारों व कुलकों को अनाज खरीदने और असीमित भण्डारण करने की छूट दे रही है, जिसका नतीजा यह होगा कि आने वाले समय में छोटे-छोटे किसान अपनी जगहों-जमीन से उजड़ जायेंगे।

'चुनावी राजनीति का भण्डाफोड़' अभियान में वक्ताओं ने आम जनता का आह्वान किया कि वे मेहनतकशों का लोक स्वराज्य बनाने के लिए इस लुटेरी व्यवस्था के समानान्तर लोक स्वराज्य पंचायतों का गठन करें। अभियान में देहाती मजदूर-किसान यूनियन और नारी सभा की सांस्कृतिक टोली द्वारा बिरहा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यह अभियान नौजवान भारत सभा और देहाती मजदूर-किसान यूनियन की ओर से आयोजित था।

पाठक साथियों से

'बिगुल' को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके अधिक से अधिक ग्राहक बनायें।
कारखानों, वर्कशापों, दफ़्तरों के गेट पर बिगुल बेचें।
बिगुल के लिए अधिक से अधिक चन्दा जुटाकर भेजें।
इसके लेखों पर अपने और अपने साथियों के विस्तृत विचार लिखकर भेजें जिससे हम इसे और सुधार सकें।
अपने इलाके के मज़दूरों की समस्याओं और उनके संघर्षों पर रिपोर्ट भेजें।
'बिगुल' की प्रतियों और बिगुल सहयोग कूपन के लिए हमें इस पते पर पत्र लिखिए।

६६ बाबा का पुरवा, पेपर मिल रोड, निशातगंज, लखनऊ — **सम्पादक 'बिगुल'**

लेनिन के साथ दस महीने

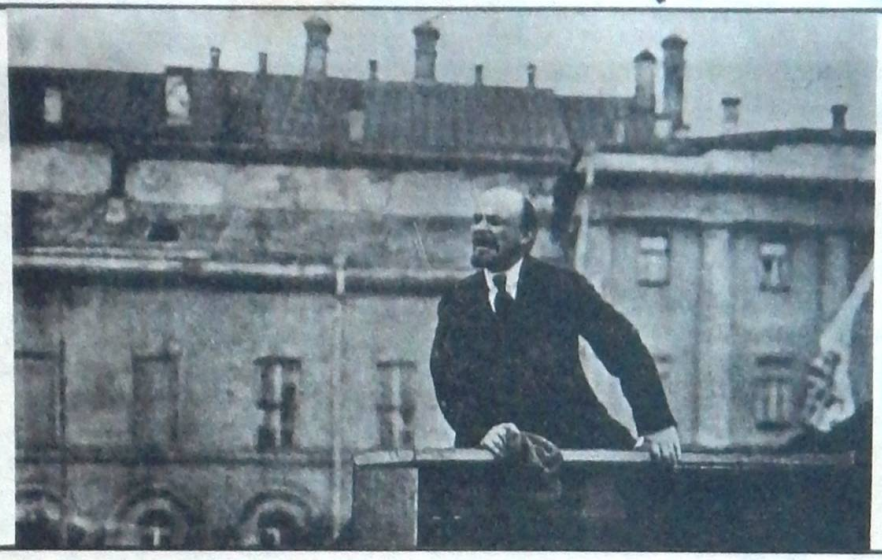

एल्बर्ट रीस विलियम्स उन पांच अमेरिकी जनों में से एक थे जो अक्टूबर क्रान्ति के तूफानी दिनों के साक्षी थे। वे 1917 के वसंत में रूस पहुंचे। उस समय से लेकर अक्टूबर क्रान्ति तक, वे तूफान के साक्षी ही नहीं बल्कि भागीदार भी रहे। इस दौरान उन्होंने व्यापक जनता के शौर्य एवं सृजनशीलता के साथ ही बोल्शेविक योद्धाओं के जीवन को भी निकट से देखा। लम्बे समय तक वे लेनिन के साथ-साथ रहे। क्रान्ति के बाद जुलाई, 1918 तक उन्होंने दुनिया भर की प्रतिक्रियावादी ताकतों से जूझती पहली सर्वहारा सत्ता के जीवन-संघर्ष को निकट से देखा।

स्वदेश लौटकर रीस विलियम्स ने दो किताबें लिखीं – 'लेनिनः व्यक्ति और उनके कार्य' तथा 'रूसी क्रान्ति के दौरान'। ये दोनों पुस्तकें एक जिल्द में 'अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन' नाम से राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी हैं।

हम रीस विलियम्स की पूर्वोक्त पहली पुस्तक का एक हिस्सा 'बिगुल' के पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

– *संपादक*

(पिछले अंक से आगे)

16 सर्वहारा वर्ग में लेनिन का जबरदस्त विश्वास

लेनिन तो निश्चय ही सर्वहारा वर्ग को क्रान्ति की संचालक शक्ति, इसका अन्तस्तल और इसका स्रोत मानते थे। नये समाज की एकमात्र आशा जनता थी। सभी इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। रूसी जन-समुदाय के लिए सामान्य रूप से प्रचलित धारणा यह थी कि वे लापरवाह और फक्कड़, अनिपुण, आलसी , अपढ़, केवल वोद्का पीने के लिए लालायित दूषित विचारों वाले, आदर्शशून्य और जमकर श्रम करने के लिए अक्षम हैं।

"अविज्ञ" जन समुदाय के बारे में लेनिन का मूल्यांकन उक्त दृष्टिकोण के सर्वथा प्रतिकूल था। वर्षों के लम्बे अर्से में लेनिन सदा ही जनता की दृढ़ता, अडिगता, अभाव सहने और बलिदान करने की उसकी क्षमता, बड़े राजनीतिक विचारों को समझने की उसकी योग्यता और उसकी अन्तर्निहित महान सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों पर बल देते रहे। एक प्रकार से जनता में उनका यह घोर विश्वास था। किस सीमा तक घटनाओं से रूस के मजदूरों में लेनिन का दृढ़ विश्वास सही सिद्ध हुआ है!

जिन पर्यवेक्षकों ने गहराई में जाकर रूस की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, उन्हे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों को समझ पाने की रूसी जनता की योग्यता से बड़ा आश्चर्य हुआ। रूट शिष्ट मण्डल* के एक सदस्य ने हैरत में आकर पूछा,"जब सभी विज्ञजन रूसी जन-समुदाय को अज्ञानी और मूर्ख समझते हैं, तो यह कैसे संभव हुआ कि जो सामाजिक दर्शन शेष दुनिया के लिए इतना नया है, उसे उन्होंने सबसे पहले ग्रहण कर लिया ?" ईसाई युवक संघ** और अन्य संगठनों की ओर से भेजे गये सैकड़ों युवकों से रूसी मजदूरों को बड़ी निराशा हुई थी। ये "ज्ञान प्रदाता" अमरीकी विश्वविद्यालयों के स्नातक थे। फिर भी उन्हें समाजवाद, संघाधिपत्यवाद और अराजकतावाद का अन्तर मालूम नहीं था, जिसका ज्ञान लाखों रूसी मजदूरों ने अपनी राजनीतिक शिक्षा के प्रारम्भ में ही प्राप्त कर लिया था।

अमरीकी प्रचारकों ने राष्ट्रपति विलसन के 14 सूत्री भाषण की लाखों प्रतियां रूस में वितरित की। मजदूरों अथवा किसानों के हाथों में इसे देते हुए वे पूछते, " इसके बारे में तुम्हारा क्या खयाल है?"

सामान्यतया वे उत्तर देते ," यह भाषण पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, परन्तु इसका कोई आधार स्तम्भ नहीं है। राष्ट्रपति विलसन के दिमाग में ऐसे आदर्श हो सकतें हैं, मगर जब तक सरकार पर मजदूरों का नियंत्रण न हो, तब तक शान्ति- सन्धि में इनमें से कोई भी आदर्श शामिल नहीं किया जाएगा।"

एक विख्यात अमरीकी प्रोफेसर ने रूसियों को ऐसे कहते सुनकर उनके अविश्वास का उपहास उड़ाया था। मगर बाद में उन्हे स्वयं अपने भोलेपन पर लज्जा आई और उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे पिछड़े हुए रूस के सुदूरवर्ती भागों की छोटी सोवियतों के वे 'गंवार लोग' अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की उनसे बेहतर जानकारी रखते हैं।

अंग्रेजो ने यह समझा कि लोगों के तात्कालिक आत्महितों की तृष्टि करने से ही उनका उल्लू सीधा हो जाएगा। वे लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए मुरब्बा, व्हिस्की और बढ़िया आटा लिए हुए अर्खांगेल्स्क पंहुचे। बुभुक्षित लोग यह उपहार पाकर प्रसन्न हुए, परन्तु जब यह बात उनकी समझ में आ गई कि उनकी आंखो में धूल झोंकने के लिए उन्हे घूस दी गयी है और इन वस्तुओं की कीमत अपनी ईमानदारी की बलि एवं रूस की स्वतंत्रता के रूप में चुकानी होगी, तो वे आक्रमणकारियों पर टूट पड़े और उन्हे अपने देश से मार भगाया।

समय ने भी रूसी जनता की दृढ़ता एवं अडिगता में लेनिन के विश्वास को सही सिद्ध कर दिया है। 1917 की क्रूर भविष्यवाणियों से आज के तथ्यों की तुलना कीजिए । उस समय सोवियतों के शत्रुओं ने यह भीषण भविष्यवाणी की थी। "तीन दिन के बाद सत्ता उनके हाथ से निकल जायेगी।" तीन दिन की जगह कई दिन गुजर गए और तब वे चिल्लाए, "सोवियतों का अस्तित्व अधिक से अधिक तीन सप्ताह तक कायम रहेगा।"उन्हे फिर से मुंह की खानी पड़ी और तब उन्होने "तीन महीने" का राग अलापा। बाद में आठ बार "तीन महीने" की रट लगाने के बाद सोवियतों के शत्रुओं ने अपने समर्थकों को यही सांत्वना दी कि अधिक से अधिक तीन वर्षों तक सोवियतों का अस्तित्व कायम रह सकेगा।

17 मजदूरों और किसानों की उपलब्धियां लेनिन की आशाओं से भी अधिक

जैसा कि कुछ लोगों का अनुमान है, सोवियत सरकार की शक्ति एवं स्थिरता सभी कानूनों के उल्लंघन तथा अज्ञात दैवी शक्ति के करिश्मों में निहित नहीं हैं। यह ठीक उसी तथ्य पर जिसकी ओर लेनिन ने संकेत किया था – मजदूरों और किसानों की ठोस उपलब्धियों पर आधारित है।

उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में लिनन का कपड़ा और दियासलाइयां बनाने की नई प्रक्रियाएं शुरू कीं और वे रूस के विस्तीर्ण दलदल के कोयले का उपयोग भी नये तरीके से करने लगे। उन्होंने विद्युत्-शक्ति संयत्रों से लेकर बिजलीघरों के निर्माण तथा बाल्टिक सागर और वोल्गा नदी के बीच लम्बी नहर की खोदाई एवं सैकड़ों मील लम्बे रेल-पथ का निर्माण तक कई प्रकार के विशाल इंजीनियरिंग उद्योगों को पूरा किया।

मजदूरों और किसानों ने फौजी क्षेत्र में सख्त फौजी अनुशासन की भावना अपना ली, जिसके फलस्वरूप लाल सेना विश्व में एक बहुत ही शक्तिशाली फौज बन गई। सर्वहारा वर्ग के इन सैनिकों का विशिष्ट नैतिक स्तर एवं उनकी अपनी आत्मदृढ़ता है। अब तक उन्होने सदा उच्च वर्गों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं। अब प्रथम बार वे सजग हो कर अपने हितों एवं विश्व के श्रम-क्लान्त और शोषित लोगों के हितों के लिए लड़ाइयां लड़ रहें हैं।

परन्तु सांस्कृतिक क्षेत्र में इन "गंवार लोगों" की उपलब्धियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहीं हैं। व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो और वह सृजन करने लगता है। नयी भावना के तीव्र स्पर्श से दसियों नये विश्वविद्यालयों, बीसियों थियेटरों हजारों पुस्तकालयों और लाखों सामान्य स्कूलों की स्थापना हो चुकी है और उनका विकास हो रहा है।

इन्हीं यथार्थताओं से प्रभावित होकर मक्सिम गोर्की सोवियतों के पक्षधर हो गये। उन्होंने लिखा है, "रूसी मजदूर सरकार के सांस्कृतिक सृजनात्मक काम का क्षेत्र और स्वरूप ऐसा होने वाला है, जिसकी मानवजाति के इतिहास में मिसाल नहीं है। भावी इतिहासकार संस्कृति के क्षेत्र में रूसी मज़दूरों के इस विगत वर्ष की शानदार उपलब्धि की सराहना किये बिना नहीं रह सकता।"

यदि यह बात भी ध्यान में रखी जाये कि जन-समदाय को किन कठिनाइयों के बीच परिश्रम करना पड़ा, तो ये उपलब्धियां और अधिक स्तम्भित करनेवाली एवं महत्वपूर्ण प्रतीत होंगी। जब सत्ता मजदूरों के हाथ में आई, तो विरासत के रूप में उन्हे दरिद्र पिछड़ा हुआ और सदियों से प्रताड़ित राष्ट्र मिला। महायुद्ध में 20 लाख हृष्ट-पुष्ट रूसी मारे गये, 30 लाख रूसी घायल एवं पंगु हुए , लाखों बच्चे अनाथ और लाखों अन्धे, बहरे और गूंगे हो गये। रेल लाइनें जगह-जगह टूटी पड़ी थीं, खानों में पानी भरा हुआ था, भोजन और ईंधन का सुरक्षित भण्डार प्रायः खत्म हो चुका था। युद्ध से अव्यवस्थित अर्थतंत्र के सामने, जो क्रान्ति से और अधिक छिन्न-भिन्न हो गया था, 1,00,00,000 सैनिकों को फौज से अलग करने की समस्या भी अचानक ही आई। देश में गल्ले की बहुत अच्छी फसल उगाई गई, मगर जापानियों, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और अमरीकियों के समर्थन से चेकोस्लोवाकिया के सैनिकों*** ने सोवियत रूस को साइबेरिया की और अन्य प्रतिक्रान्तिवादियों ने उक्रइना की गल्ले की फसलों से काट लिया। उन्होने कहा,"अब भूख के हड्डीले हाथ लोगों के गले पकड़ लेंगे और तब उन्हे होश आएगा।"चर्च को राज्य से अलग करने के अपराध में सोवियतों को धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। पुराने अधिकारियों ने उनके विरूद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयां कीं, बुद्धिजीवियों ने उनकी ओर से मुंह फेर लिया और साम्राज्यवादी मित्र राष्ट्रों की फौजों ने नाकेबन्दी कर दी। मित्र राष्ट्रों ने सभी प्रकार की धमकियों, घूसखोरी एवं हत्याओं द्वारा उनकी सरकार को उलट देने की कोशिशें कीं। अंग्रेजों के भाड़े के टट्टुओं ने रेलों के पुल उड़ा दिये, ताकि बड़े नगरों में भोजन तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां न पहुंच सकें और फ्रांसीसी गुप्तचरों ने अपने कौन्सिल कार्यालयों के संरक्षण में रेल इंजनों के बियरिंगों में रेत डालकर यातायात को नुकसान पहुंचाया।

लेनिन ने इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए कहा, "हां, हमारे शत्रु शक्तिशाली हैं, परन्तु उनके विरुद्ध हमारे पास सर्वहारा वर्ग की इस्पाती ताकत है। अभी विशाल जनता का अधिकांश वास्तविक रूप में सजग और क्रियाशील नहीं है। इसका कारण भी स्पष्ट है। वे युद्ध से परिक्लान्त, भूखे और थके हुए हैं। क्रान्ति का प्रभाव अभी उतना गंभीर नहीं है, मगर विश्रान्ति के साथ बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन होगा। यदि समय रहते यह परिवर्तन हो गया, तो सोवियत जनतंत्र बच जायेगा।"

लेनिन की दृष्टि से 1917 के अक्टूबर की घटना – जन समुदाय का अद्भुत ढंग से सत्तारूढ़ होना – क्रान्ति नहीं थी। परन्तु जब यह जन-समुदाय अपने लक्ष्य के प्रति सजग होकर अनुशसित होने लगेगा, व्यवस्थित रूप से काम में जुट जायेगा और अपनी महान सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का कर्मक्षेत्र में उपयोग करने लगेगा – तब वास्तविक क्रान्ति होगी।

क्रान्ति के उन प्रारम्भिक दिनों में लेनिन को इस बात का कभी पक्का विश्वास नहीं था कि सोवियत जनतंत्र की रक्षा हो गई। उन्होंने जोर देकर कहा, "दस दिन और! तब हमारा जनतंत्र कम से कम पेरिस कम्यून जितने दिनों तक तो कायम रहेगा ही।" पेत्रोग्राद में सोवियतों की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस में अपना भाषण शुरू करते हुए उन्होंने कहा, "साथियो, इस बात पर गौर कीजिए कि पेरिस कम्यून 70 दिनों तक टिका रहा। हमारा सोवियत जनतंत्र उससे दो दिन अधिक का हो गया है।"

महान रूसी कम्यून ने सत्तर दिनों के दस गुने से भी लम्बी अवधि तक अपने सभी शत्रुओं के खिलाफ प्रतिरोधात्मक मोर्चा लिया। लेनिन को सर्वहारा वर्ग की दृढ़ता, धैर्य, अडिगता, वीरता और आर्थिक, सैनिक एवं सांस्कृतिक क्षमताओं में पूर्ण विश्वास था। उसकी उपलब्धियों केवल उसके उत्साहपूर्ण विश्वास की परिचायक नहीं थीं। वे लेनिन के लिए भी विस्मयकारी थीं।

क्रमशः

*रूट शिष्टमण्डल – एक विशेष अमरीकी शिष्टमण्डल, जो 1917 में रूस भेजा गया था और जिसका नेतृत्व ई. रूट (1845-1937) ने किया था। इसका उद्देश्य रूस को युद्ध से अलग होने से रोकना और अस्थाई सरकार को क्रान्तिकारी आंदोलन से लड़ने में सहायता प्रदान करना था।

**ईसाई युवक संघ(Young Men's Christian Association) – एक पूंजीवादी युवक संगठन। रूस में इसके प्रतिनिधियों ने धार्मिक और सोवियत विरोधी प्रचार किया।

***प्रथम विश्व-युद्ध के समय रूस में चेक एवं स्लोवाक युद्धबंदियों को शामिल कर चेकोस्लोवाक फौजी टुकड़ियां गठित की गई थीं। 1918 में मई के महीने में समाजवादी क्रान्तिकारियों और मेंशेविकों के सक्रिय समर्थन से फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवादियों ने वोल्गा क्षेत्र तथा साइबेरिया में चेकोस्लोवाक टुकड़ियों में प्रतिक्रान्तिवादी विद्रोह संगठित किया।

गुजरात में खून की होली खेलने वाले धर्मध्वजाधारी पूंजी के चाकर हैं, हैवानियत के पुजारी हैं

मेहनतकश भाइयो! इन्सानियत के इन दुश्मनों को पहचानो!

(विशेष संवाददाता)

दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली आकर प्रधानमंत्री जी को यह भरोसा दिलाकर चलते बने कि गुजरात में हालात काबू में हैं। खूनखराबा रोकने में कोई ढिलाई नहीं हुई है और जल्दी ही पूरी तरह अमन-चैन कायम हो जायेगा। जबकि हालत यह है कि गोधरा काण्ड के एक महीने बाद भी धर्मध्वजाधारी 'म्लेच्छों' के खून से तिलक लगा रहे हैं। जबकि पूरी तरह तबाह-बरबाद हो चुके एक लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में भी सरकार नाम की चिड़िया के फुदकने की बाट जोह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को संघ परिवार के लाडले मुख्यमंत्री की बातों पर पूरा भरोसा हो गया है।

नरेन्द्र मोदी को 'क्लीन चिट' देकर प्रधानमंत्री जी ने भी तमाम अखबारों, टी.वी.चैनलों की रिपोर्टों को झूठा करार दे दिया है। ये सारी रिपोर्टें झूठी हैं कि किस तरह अहमदाबाद, वड़ोदरा, भरुच आदि जगहों पर छापा-तिलक-त्रिशूलधारी रामभक्तों ने घरों-दुकानों-इंसानों की होली जलायी, कहीं किसी गर्भवती स्त्री का पेट चीरकर गर्भ में पल रहे शिशु की गर्दन काट डाली, कहीं 19 सदस्यों वाले एक संयुक्त परिवार के घर में पानी भरकर बिजली का करंट दौड़ा दिया, 'मातृशक्ति' के पुजारियों ने किस तरह सामूहिक बलात्कार के सारे कीर्तिमान तोड़ डाले, किस तरह पुलिस-प्रशासन जान बचाने की गुहार करते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के नाम पर कातिलों के सुपुर्द करता रहा, दंगाइयों पर काबू पाने के नाम पर सिर्फ एक समुदाय के लोगों को पुलिस चुन-चुनकर निशाने बनाती रही ... यानी मीडिया में आयी इस तरह की सारी खबरें झूठी हैं कि गुजरात राज्य मशीनरी दंगाइयों पर काबू पाने की बजाय उन्हें खुले हाथ खेलने का पूरा मौका देती रही। मीडिया में आयी ऐसी सारी खबरों-रिपोर्टों को मोदी तो झूठा करार दे ही रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी मोदी के बगल में खड़े हो गये हैं।

जिस किसी का भी दिमाग "हिन्दू राष्ट्रवाद" के जुनून में फिर नहीं गया है, जिस किसी की भी आंखों पर धार्मिक कट्टरपंथ की पट्टी नहीं बधी हुई है, उसे इस पर विश्वास हो ही नहीं सकता कि गोधरा काण्ड की "स्वाभाविक प्रतिक्रिया" में गुजरात में हैवानियत का नंगानाच हुआ। गुजरात में गोधरा के बहाने राज्य द्वारा प्रायोजित फासिस्ट कत्लेआम हुआ है। योजनाबद्ध ढंग से मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सफाया किया गया है। ठीक उसी तरह जैसे नाजी जर्मनी में आर्य जाति की श्रेष्ठता के नाम पर यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। समूचे मीडिया और कई स्वतंत्र जांच दलों ने इसी सच्चाई को पुष्ट किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इन पर विश्वास नहीं है। मोदी ने उन्हें भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम 'क्रिया-प्रतिक्रिया' के नियम – का मर्म समझा दिया है। प्रधानमंत्री जी इसे बखूबी समझ भी गये हैं। आखिर मोदी भी उनके अपने ही "परिवार" के सदस्य हैं – उस परिवार के जिसके दबाव में काम करने का आरोप लगते ही वे भरी संसद में दुर्वाशा ऋषि से भी प्रचण्ड क्रोध से फुफकार उठते हैं।

बहरहाल, सच्चाई अगर चीख-चीखकर भी बोलती हो तो उस पर कान न देना और किसी झूठ को हजार बार बोलकर उसे सच साबित करने की कला में प्रधानमंत्री जी का "परिवार" माहिर है लेकिन गुजरात की सच्चाई इतनी उजागर है कि प्रधानमंत्री जी के "परिवार" के पुरखे हिटलर और गोयबल्स भी झुठला नहीं सकते। गुजरात में गोधरा काण्ड के बाद जो हुआ वह देश में पहले हुए दंगों जैसा कुछ नहीं था। गुजरात में दो समुदायों की आम आबादी मजहबी जुनून में एक दूसरे को मरने-मारने पर उतारू

नहीं हुई थी। बाकायदा एक रणनीति बनाकर योजनाबद्ध ढंग से राज्य मशीनरी के सहयोग से एक समुदाय के लोगों के जान-माल का सफाया किया गया। यह राजकीय संरक्षण में हुआ फासिस्ट कत्लेआम है, और दूसरा कुछ नहीं।

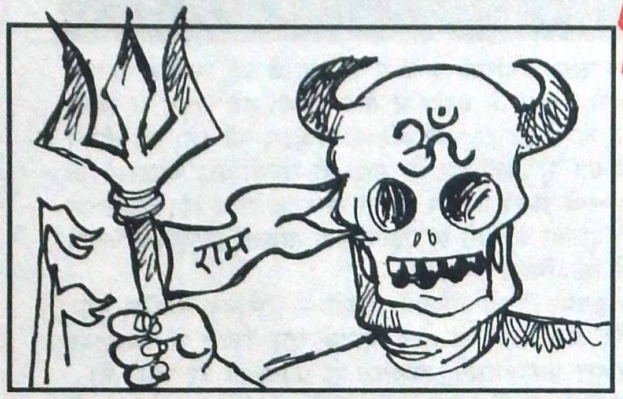

गुजरात में हिन्दुत्व के रणबांकुरों ने मुसलमानों का सफाया अभियान कितने योजनाबद्ध ढंग से चलाया है इसका एक-दो नहीं अनेक सबूत हैं। "दंगाइयों" के गिरोहों के पास कम्प्यूटराइज्ड सूचियां थीं जिनमें मुसलमानों के घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पते और नक्शे थे। मुसलमान आबादी की आर्थिक रूप से कमर तोड़ देने के लिए उन्होंने चुन-चुनकर उनकी दुकानों को आग के हवाले किया, लूटपाट की और तबाह किया। यह उनकी योजना का हिस्सा था इसे उस पर्चे से भी समझा जा सकता है जिसे किसी बेनाम रामभक्त की ओर से जारी किया गया था। पर्चे में खुल्लमखुल्ला लिखा था कि आतंकवादियों (मुसलमानों) की आर्थिक रूप से कमर तोड़ देने के लिए सच्चे राष्ट्रवादियों (हिन्दुओं) को क्या-क्या करना चाहिए। हिन्दुओं को मुसलमानों की दुकानों से कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, उनके साथ किसी तरह का सामाजिक रिश्ता नहीं रखना चाहिए, यहां तक कि अगर किसी फिल्म का निर्माता-निर्देशक-अभिनेता-अभिनेत्री-गीतकार-संगीतकार मुसलमान हो तो उस फिल्म को नहीं देखना चाहिए वगैरह-वगैरह। इस तरह के अनेक तालिबानी फरमानों से भरा पर्चा विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बांट रहे थे। प्रशासन को पूरी खबर थी पर वह आंखें मूंदे रहा।

इस पर्चे में नफरत फैलाने, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को भड़काने की दूसरी और भी कई बातें थीं। हिन्दुओं के लिए तालिबानियों की तर्ज पर बाकायदा एक आचार-शास्त्र लिखा हुआ था। हिन्दू पिताओं को एक सलाह यह दी गयी थी कि वे अपने जवान बेटियों पर पूरी निगरानी रखें जिससे वे किसी मुसलमान लड़के के चक्कर में न फंसे। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम क्या होगा ऐसा उन्होंने अमल में लाकर दिखा दिया। चौबीस मार्च को अखबारों में एक खौफनाक खबर आयी कि हिन्दू राष्ट्र के झण्डाबरदारों ने 25 वर्षीय गीता बेन नाम की एक हिन्दू युवती को बर्बरतापूर्वक इसलिए मार डाला कि वह मुन्ना नामक एक मुसलमान लड़के के साथ रहती थी। वहशियों के एक गिरोह ने पहले इस लड़की के घर पर धावा बोलकर दोनों को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन मुन्ना किसी तरह बचकर भाग निकला लेकिन जान बचाने के लिए भागती लड़की को पास के एक बस स्टाप पर वहशियों ने धर दबोचा। पहले उन्होंने उसे बांधकर निर्वस्त्र किया फिर उसके पेट में चाकू घोंपकर मार डाला। इस घटना में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें भाजपा के दो नेता भी शामिल हैं।

ऐसा ही वहशियाना कत्लेआम हुआ है गुजरात में, जिसमें गैरसरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग दो हजार लोग मारे गये हैं जबकि सरकारी सूत्र सिर्फ 750 लोगों के मरने की बात कह रहे हैं। इस बार गुजरात में जो हुआ है उसकी तुलना अतीत के किसी भी दंगे से नहीं की जा सकती। 1984 में इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद भी सिखों का जो कत्लेआम हुआ था उसमें भी काफी हद तक स्वतःस्फूर्तता था। कांग्रेसियों ने जगह-जगह उन्मादी भीड़ को उकसाने-भड़काने का ही काम किया था। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद सूरत आदि जगहों पर जो बर्बरता हुई थी वह भी इतना संगठित-योजनाबद्ध नहीं था। गुजरात में इस बार जो हुआ वह इससे आगे की चीज है। इस बार संघ परिवार की फासिस्ट मशीनरी और राज्य मशीनरी के बीच खतरनाक तालमेल से योजनाबद्ध ढंग से मुस्लिम आबादी का 'सफाया' किया गया है। पुलिस की भूमिका भी पहले के दंगों से बिल्कुल अलग थी। पहले मेरठ (मलियाना) आदि जगहों पर भी पुलिस-पी.ए.सी. ने एक हिन्दू पार्टी के रूप में मुसलमानों का कत्लेआम किया था। लेकिन यह देश की सामाजिक संरचना के साम्प्रदायीकरण के अंग के रूप में पुलिस मशीनरी के साम्प्रदायीकरण के चलते होने वाली स्वतःस्फूर्त कार्रवाइयां थीं। लेकिन गुजरात में बाकायदा पुलिस के सिपाहियों को कत्लेआम में मदद करने के निर्देश दिये गये थे। यह बात बिल्कुल ठीक ही कही जा रही है कि गुजरात देश में फासिज्म की एक खूनी प्रयोगशाला बन गया है। राज्य मशीनरी ने हर तरीके से दंगाइयों की मदद की। आगजनी के लिए दंगाइयों को हजारों गैस सिलिण्डर कहां से मिले? चुन-चुन कर सफाया करने के लिए कम्प्यूटराइज्ड सूचियां, नक्शे और जमीन-जायदाद के कागजात किसने उपलब्ध कराये? इसे समझना बिल्कुल कठिन नहीं।

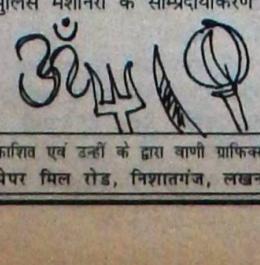

मेहनतकश भाइयो! यह है हिन्दू राष्ट्रवाद का खूंख्वार चेहरा। ये हिन्दू राष्ट्र के झण्डाबरदार, धर्मध्वजाधारी हैवानियत के पुजारी हैं। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के अलमबरदार कातिल फासिस्ट गिरोहों के सिवा कुछ नहीं है। इनकी चाल-चेहरा-चरित्र को समझने के लिए अब और कितनी मिसालें चाहिए?

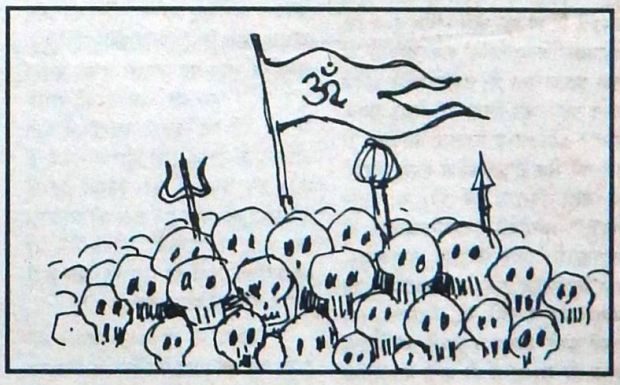

हिन्दू राष्ट्रवाद के ये पताकाधारी देशी-विदेशी पूंजी के चाकर हैं, मेहनतकश भाइयों को इसे भी अच्छी तरह समझ लेना होगा। देश के मेहनतकशों और तमाम प्राकृतिक सम्पदा को लूटने के लिए विदेशी पूंजी की अगवानी करने वाले, देशी-विदेशी मुनाफाखोरों को बेलगाम लूटने का मौका देने के लिए श्रम कानूनों को बदलने वाली जमात अगर देशभक्त

होने का डंका बजाये तो इस बेहया जमात के खिलाफ मेहनतकशों को क्या नफरत से भर नहीं जाना चाहिए। तहलका काण्ड के अपराधियों और कफनचोरों की देशभक्ति की हवा तब निकल गयी, जब चार विधानसभा चुनावों में इस जमात की मिट्टी पलीद हो गयी, तब उसके सामने यही एक चारा बचा था कि देश को दंगों की आग में झोंक दें। क्या यह अनायास था कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और संसद में बजट पेश होने के साथ ही गुजरात जल उठा। गोधरा काण्ड को लेकर तमाम स्वतंत्र जांच दलों ने जो सवाल उठाये हैं अगर उनके जवाब नहीं मिलते तो क्या यह अनुमान भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह भी हिन्दू फासिस्टों के किसी षडयंत्र का हिस्सा था? गोधरा पहले से ही संवेदनशील जगह माना जाता रहा है। फिर जब लगातार तीन-चार ट्रेनों से गुजरने वाले कारसेवक गोधरा रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचाते रहे थे, मुसलमान वेण्डरों को बेइज्जत कर रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे, तो सुरक्षा के पर्याप्त इन्तजाम क्यों नहीं किये गये? इससे अगर यह नतीजा निकाला जाये कि गुजरात सरकार फासिस्ट कत्लेआम के लिए कोई बहाना चाहती थी और गोधरा काण्ड से वह बहाना मिल गया।

साथियो! इतिहास गवाह है कि फासिस्ट जमातों के निशाने पर अल्पसंख्यक ही नहीं मेहनतकशों के क्रान्तिकारी आंदोलन हैं। बल्कि सच तो यह है कि वे मेहनतकशों के क्रान्तिकारी आंदोलन को ही अपना दुश्मन नम्बर एक मानते हैं। इसीलिए वे धार्मिक-नस्ली भेदभाव उभारकर मेहनतकशों की एकता को तोड़ डालना चाहते हैं। आज यह जरूरत भाजपा और उसके बिरादरों को ही नहीं समूचे शासक पूंजीपति वर्ग को है कि हर हथकण्डे अपनाकर मेहनतकशों को खण्ड-खण्ड बांट दिया जाये और देशी-विदेशी पूंजी की सबसे वफादार चाकर भाजपा एण्ड कम्पनी इसी काम में जुटी हुई है। इस हकीकत को अच्छी तरह हमें समझ लेना होगा।

लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि दुनिया में इन्सानियत के दुश्मन फासिस्टों को मेहनतकशों की क्रान्तिकारी सेनाओं ने ही धूल चटायी है और इतिहास में उनके लिए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है – यानी इतिहास की कूड़ेदानी में। उन्हें यही डर सता रहा है। इसीलिए वे पोटो जैसा कानून भी पास कर रहे हैं। एक बार फिर इतिहास की यह जिम्मेदारी मेहनतकशों को ही उठानी होगी। उन्हें इन कातिल गिरोहों के बहकावे में न आते हुए अपनी फौलादी एकता कायम करने की कोशिश तेज कर देनी होगी। मन्दिर-मस्जिद के हवाई मुद्दों की जगह रोजी-रोटी और जिन्दगी से जुड़े तमाम बुनियादी मुद्दों के आधार पर नये सिरे से एकजुट होने का काम तेज कर देना ताकि इस बार उन्हें फैसलाकुन शिकस्त दी जा सके और इसके लिए जरूरी है कि देश के मेहनतकश पूंजीवादी निजाम को ही उखाड़ फेंकने की तैयारी में जुट जायें।

इसके साथ ही जनतांत्रिक अधिकारों से जुड़े तमाम ईमानदार संगठनों-व्यक्तियों को भी आज यह बात पहले से अधिक साफ-साफ समझनी होगी कि उन्हें भी अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग अलापने के बजाय एकजुट होना होगा और मेहनतकशों के आन्दोलनों की धुरी के इर्द-गिर्द अपनी स्पष्ट भूमिका तय करनी होगी। फासिज्म विरोधी एक व्यापक संयुक्त मोर्चा भविष्य में जिस भी रूप में उभरकर सामने आयेगा, एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर इसकी धुरी मेहनतकशों का आन्दोलन नहीं बनेगा तो लड़ाई को कारगर कतई नहीं बनाया जा सकता। आज इसी दिशा में आगे बढ़ना समय की मांग है।

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डा. दूधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वाणी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग : कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ।
संपादक मण्डल : डा. दूधनाथ, मुकुल। सम्पादकीय पता : 69, बाबा का पुरवा, पेपर मिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006, सम्पादकीय उपकार्यालय : जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ।